● वर्ष-5
● अंक-156
रायपुर, शुक्रवार
13 फरवरी 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत...

दोनों सदन विपक्षी हंगामा के भेंट चढ़ी

नईदिल्ली। संसद में आज सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के कई सांसदों का कहना है कि वे बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू समेत विभिन्न विषयों तुरंत चर्चा चाहते हैं।

विपक्ष ने राज्यसभा में अन्य सभी संसदीय कार्यों को रोककर सबसे पहले इन मुद्दों पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था। विपक्षी सांसदों के इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा में भी रहा। लोक लोकसभा में भी

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए। विपक्ष के ये सांसद चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।

सदन में हो रहे हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार विपक्षी सांसदों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह किया गया। नाराज विपक्षी सांसद जब अपने स्थानों पर वापस नहीं गए तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं, राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने बताया कि उन्हें आज यानी सोमवार को चर्चा के लिए नियम 267 के अंतर्गत 29 नोटिस मिले हैं।

नियम 267 के अंतर्गत सदन की शेष सभी कार्यवाही को स्थगित करके संबंधित विषय पर चर्चा कराई जाती है। इस नियम के अंतर्गत कराई जाने वाली चर्चा के उपरांत वोटिंग का भी प्रावधान होता है। उप सभापति ने बताया कि उन्हें पांच अलग-अलग विषयों पर चर्चा के नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही उप सभापति ने कहा कि 11 विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए नोटिस में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। वहीं बचे हुए 18 नोटिसों में से कई नोटिस ऐसे मामलों को लेकर थे जिनकी सुनवाई अदालत में चल रही है।

एफआईआर करो या सदस्यता लो, मैं नहीं डरूंगा: राहुल

संसद में अमेरिका से हुए ट्रेड डील को लेकर गंभीर सवाल उठाने के बाद सरकार और भाजपा की ओर से अपने उपर हो रहे भारी चौतरफा हमलों के बावजूद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस डील में किसानों और देश के हितों की बलि चढ़ाए जाने के अपने आरोपों को दुहराया है। लोकसभा की उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए भाजपा सदस्य की ओर से दिए गए प्रस्ताव के बाद गुरूवार को राहुल गांधी ने सत्तापक्ष को जवाबी चुनौती देते हुए कहा चाहे उन्हें गाली दी जाए, एफआईआर हो, विशेषाधिकार हनना प्रस्ताव लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि संसद में ट्रेड डील पर उन्होंने सच्चाई बोली है। भाजपा और सरकार को चाहे यह सच्चाई अच्छी न लगे और उनके खिलाफ जो कुछ भी करना है वह कर ले मगर वे अपनी बातों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के मंत्रियों-भाजपा नेताओं के सियासी हमलों के बाद गुरूवार शाम एक्स पर जारी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जो ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीने, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान-विरोधी है।

निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया

नई दिल्ली। भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक मोशन पेश किया है, जिसमें विपक्षी नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। डॉ. दुबे ने कहा सोरोस फाउंडेशन और देश को टुकड़े करने वाले ताक़तों के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत का विभाजन करना चाहते हैं। इसलिए मैंने लोकसभा के नियम 352(5) और 353 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया। सोरोस फाउंडेशन व देश को टुकड़े करने वाले ताक़तों के साथ मिलकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भारत का विभाजन करना चाहते हैं।

तीनों सेनाओं को मिलेगा आधुनिक हथियारों का बड़ा पैकेज

राफेल डील पर मुहर

नईदिल्ली। रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक में मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को नए राफेल लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। फ्रांस के साथ होने वाले इस सौदे समेत करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

डीएसी बैठक में बड़े फैसले

नई दिल्ली में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वायुसेना के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलें और एयर-शिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड प्स्यूडो सैटेलाइट (एएस-एचएपीएस) खरीदने को मंजूरी दी गई। थलसेना के लिए एंटी-टैंक माइन, टी-72 टैंक, बीएमपी-द्वद्ब और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहॉल को भी स्वीकृति मिली।

राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान वायुसेना को लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करेंगे। बीते वर्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल की मदद से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अधिकतर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर दूर से सटीक वार करने में सक्षम होंगी, जबकि एएस-एचएपीएस प्रणाली निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य संचार को मजबूत करेगी।

थलसेना को आधुनिक हथियार

थलसेना के लिए एंटी-टैंक माइन 'विभव' को मंजूरी दी गई है, जो दुश्मन के टैंकों और भारी वाहनों को रोकने में प्रभावी होगी। इसके अलावा टी-72 टैंक, बीएमपी-द्वद्ब और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहॉल से उनकी क्षमता और सेवा अवधि बढ़ेगी।

नौसेना और तटरक्षक बल को भी मजबूती

भारतीय नौसेना के लिए 4 मेगावॉट मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जेनरेटर और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान पी-8आई की खरीद को मंजूरी मिली है। पी-8आई विमान पनडुब्बी रोधी अभियान, समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेंगे।

पावर जेनरेटर 'मेक-1' श्रेणी के तहत भारत में विकसित किए जाएंगे, जिससे विदेशी निर्भरता घटेगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय तटरक्षक बल के डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जिससे समुद्री निगरानी और प्रभावी होगी।

रक्षा मंत्रालय का मानना है कि ये फैसले भारत की सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है और धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित इस धरा को हमारी सरकार सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में सिक्किम राज्य से अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे पत्रकारों के दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया और उनसे छत्तीसगढ़ को लेकर ढेर सारी बातें साझा की। उन्होंने सभी अतिथियों को राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिवादन किया।

ढाका-17 सीट से तारिक रहमान जीते

बांग्लादेश। बांग्लादेश में आज 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान कराए गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के करीब डेढ़ साल बाद पहली बार आम चुनाव कराए गए हैं। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। अवामी लीग चुनाव से बाहर है। करीब नौ लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। कई जगहों पर हिंसा और धमाके की खबरें हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर मतदान के आधिकारिक समय शाम साढ़े चार बजे तक 40 फीसदी से अधिक मतदान कराए गए हैं। चुनाव आयोग देर रात आधिकारिक एलान करेगा, ऐसे में अंतिम आंकड़े में बदलाव संभव है। अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें बांग्लादेश चुनाव से जुड़े सभी अहम अपडेट्स

बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य शैरुल कबीर खान के अनुसार, बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका-17 निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। गुरुवार सुबह, तारिक रहमान ने राजधानी के गुलशन मॉडल हाई स्कूल और कॉलेज केंद्र में 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में अपना वोट डाला। वे सुबह करीब 9=30 बजे केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला। उनकी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान ने भी उनके साथ मतदान किया था।

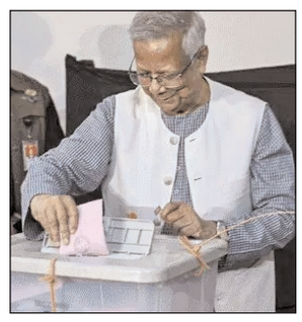

प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर (धान की बाली) 35 मतदान केंद्रों से 39,101 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार को 25,976 वोट मिले हैं, जबकि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के खादिमुल इस्लाम को 705 वोट मिले हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 185 मतदान केंद्र हैं।

बांग्लादेश के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में बीएनपी के स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमद कॉक्स बाजार-1 (चकड़िया-पेकुआ) से भारी बढ़त बनाए हुए हैं। 177 मतदान केंद्रों में से 74 केंद्रों के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, धान की बाली के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे सलाहुद्दीन को 121,119 वोट मिले हैं।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली,। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करने वाले है। वे शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ में कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर करीब 1.30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नामकरण करने वाले है। इसके बाद वे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करने वाले है। यह उद्घाटन भारत के प्रशासनिक शासन संरचना में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। यह प्रधानमंत्री के एक मॉडर्न, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस इकोसिस्टम बनाने के वादे को दिखाता है। कई दशकों से कई जरूरी सरकारी ऑफिस और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा एरिया में अलग-अलग जगहों पर बने हुए थे और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते थे। इससे ऑपरेशनल खामियां, कोऑर्डिनेशन की चुनौतियां, बढ़ते मेंटेनेंस खर्च और काम न कर पाने लायक स्थिति बनी हुई थी। लेकिन नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के अंदर प्रशासनिक कार्यों को एक साथ करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं।

सामाजिक न्याय संविधान की आत्मा: खरगे

नई दिल्ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में जातिगत भेदभाव का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों के उत्थान की बातें अक्सर की जाती हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन्हें जमीन पर उतारने की ठोस पहल हो। सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा है और इसकी रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ओडिशा की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इक्कीसवीं सदी में जब हम सामाजिक विकास और एकता की बात करते हैं, तब ऐसी घटनाएं हमें आईना दिखाती हैं। उन्होंने बताया कि ओडिशा के एक आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले तीन महीनों से बहिष्कार चल रहा है, क्योंकि वहां भोजन एक दलित महिला हेल्पर और कुक द्वारा तैयार किया जा रहा है। समुदाय विशेष के कुछ लोग अपने बच्चों को वह भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की परीक्षा है।

लालू, राबड़ी, तेजस्वी को लारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत

नई दिल्ली। लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है।यह केस लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरे 16 आरोपियों के खिलाफ है। अब इस मामले में अदालत 3 मार्च को फैसला दे सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले, आआरसीटीसी घोटाले के मामले में बुधवार (11 फरवरी) को आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पूर्व रेल मंत्री नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया। सीबीआई ने तर्क दिया था कि लालू सहित अन्य यह तर्क देकर मुकदमें से बच नहीं सकते कि जब ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था तब उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं थी। निर्णय के खिलाफ लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में संज्ञान लिया।

अरावली को छूने की किसी को नहीं मिलेगी अनुमति: सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरवार को हरियाणा सरकार के अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित जू सफारी प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि अरावली को किसी भी कीमत पर छूने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि जू सफारी से जुड़े मामले को तब ही देखा जाएगा जब अरावली रेंज की परिभाषा विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट कर दी जाएगी।हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 10,000 एकड़ से घटाकर 3,300 एकड़ किया है और इसे केंद्रीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करना चाहते हैं। खंडपीठ ने कहा हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। जब तक परिभाषा अंतिम नहीं होती, हम किसी को अरावली छूने की अनुमति नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अरावली केवल हरियाणा या राजस्थान की नहीं है, बल्कि यह कई राज्यों में फैली हुई।

बोर्ड ऑफ पीस के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा भारत

नईदिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता उन्हें मिला है। फिलहाल भारत उसके हरेक पहलू पर नजर बनाए हुए है और उसकी समीक्षा कर रहा है। उन्होंने गुरुवार को ये बातें एमईए की नियमित ब्रीफिंग में कहीं। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा, हमारे पास अमेरिकी सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है। हमसे आप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को कहा गया है। हम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। भारत ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का निरंतर समर्थन किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने उन सभी पहलों का समर्थन किया है जो गाजा समेत पूरे क्षेत्र में दीर्घकालिक और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। वहीं, इस्लामाबाद ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो यूएस बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में हिस्सा लेने वाशिंगटन जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएस में होने वाली बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में शामिल होंगे।

पड़ोसी प्रथम नीति और चिंताएं

दक्षिण एशिया में भारत को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय सहयोगी बनना होगा

केएस तोमर

भारत अपने पड़ोस में यदि अकेला पड़ गया है, तो यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह दशकों पुरानी कूटनीतिक लापरवाही, रणनीतिक रूप से कम प्रतिक्रिया व राजनीतिक इरादों को ठोस नतीजों में बदलने में लगातार नाकामी का मिला-जुला नतीजा है। नई दिल्ली क्षेत्रीय नेतृत्व की ख्वाहिश रखती है, पर वह सद्भावना को स्थायी प्रभाव में बदलने में हिचकिचाती रही है, जिससे चीन को रणनीतिक शून्य को भरने का मौका मिल गया है। भारत ने उस जगह को छोड़ दिया है, जिसे कभी उसका निर्विवाद प्रभाव क्षेत्र माना जाता था।

विदेश नीति के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का लेन-देन वाला रवैया, जिसमें अचानक बदलाव, चुनिंदा जुड़ाव और अल्पकालिक फायदे को प्राथमिकता देना शामिल है, ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय समीकरणों को बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान के साथ सामरिक बातचीत फिर से शुरू करने की ट्रंप की नई इच्छा (जो आतंकवाद विरोधी नजरिये, अफगान संकट के असर या कूटनीतिक सौदेबाजी से प्रेरित है) आतंकवाद के मुद्दे पर इस्लामाबाद को कूटनीतिक तौर पर अलग-थलग करने की भारत की कोशिशों को कमजोर करती है। इस अस्पष्टता के साथ ही बहुपक्षीय फ्रेमवर्क के प्रति ट्रंप की कम होती प्रतिबद्धता और चीन पर लगातार बदलते रुखों ने छोटे दक्षिण एशियाई देशों को प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच ज्यादा आक्रामक तरीके से संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसे-जैसे वाशिंगटन का क्षेत्रीय रुख बदलता है, भारत का अपने आस-पड़ोस में नेतृत्व का दायरा सिकुड़ता जाता है, जिससे नई दिल्ली को उस बढ़ी हुई अनिश्चितता को प्रबंधित करना पड़ता है, जो इस क्षेत्र से बहुत दूर से आने वाली नीति की वजह से पैदा होती है। भारत को तुरंत वास्तविकता, विनम्रता और लगातार बातचीत पर आधारित सुधार की जरूरत है।

पहला कदम है उच्च-स्तरीय राजनीतिक वार्ता। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ढाका, कोलंबो, काठमांडो, नेप्यीडॉ और माले जैसी राजधानियों की यात्राएं फिर से एक खास इरादे के साथ शुरू होनी चाहिए।

घरेलू राजनीति में कथित पक्षपात की जगह राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। दूसरा, लंबित कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। तीस्ता समझौता, नेपाल व भूटान के साथ क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी और म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर को कूटनीति से आगे बढ़ाना होगा। भारत को चीन के कर्ज पर आधारित मॉडल से खुद को अलग दिखाने के लिए, ऋण के बजाय अनुदान पर आधारित एक दक्षिण एशियाई आर्थिक सहायता कोष बनाना चाहिए। तीसरा, सैन्य कूटनीति को फिर से शुरू करना चाहिए-संयुक्त अभ्यास, अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और सस्ते रक्षा हथियारों की आपूर्ति को चीनी हथियारों के विकल्प के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। भारत को भरोसेमंद रक्षा भागीदार के तौर पर अपनी पहचान फिर से बनानी चाहिए, खासकर श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के लिए। चौथा, भारत को सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल में जान डालनी चाहिए। क्वाड व जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ मिलकर, भारत बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और समुद्र के नीचे पारदर्शी व समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकता है। पांचवां, छात्रवृत्ति, यूथ एक्सचेंज, बॉलीवुड, योग और क्रिकेट कूटनीति के जरिये सांस्कृतिक कूटनीति को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। छठा, भारत को बहुपक्षीय और मीडिया मंचों पर अपनी बात रखने की जगह वापस पानी होगी। भारत को एफएटीएफ से लेकर ब्रिक्स व बिम्सटेक तक, कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान के आतंकी जुड़ाव को दुनिया के सामने लाना चाहिए। एक नई मीडिया रणनीति के तहत चीन-पाकिस्तान के दुष्प्रचार का त्वरित मुकाबला करना चाहिए, जिसमें स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री, क्षेत्रीय इन्फ्लुएंसर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए फंडिंग शामिल हो। सातवां, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बहुत जरूरी है। अरुणाचल, लद्दाख और सिक्किम में रणनीतिक सड़कें और निगरानी व्यवस्था उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि अंडमान, सेशेल्स, मॉरीशस और संभावित रूप से मेडागास्कर में भारत की समुद्री ताकत को मजबूत करना।

भारत की रणनीतिक नाकामियां ऐसी नहीं हैं, जिन्हें ठीक न किया जा सके, पर वे सबक सिखाने वाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पता चला कि जब कूटनीतिक सहमति या नैरेटिव पर दबदबा न हो, तो सैन्य ताकत की भी अपनी सीमाएं होती हैं। भारत को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय सहयोगी बनना होगा, जो सुनता है।

मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर किया चक्काजाम

■ मंगल कार्बन प्लांट में ब्लास्ट से पिता, पुत्र और 9 माह की बच्ची समेत चार की मौत

रायगढ़। खरसिया के मंगल कार्बन प्लांट में हुए भीषण ब्लास्ट की घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान 9 माह की मासूम के बाद तीन अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया। पिता, पुत्र एवं 9 माह की मासूम बच्ची की मौत एक ही परिवार पर असहनीय आघात है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्हें संतोषजनक न्याय एवं पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। कंपनी प्रबंधन ने कुल 12-12 लाख (प्रत्येक मृतक के लिए) मुआवजा राशि की घोषणा की है। हमारी मांग है कि प्रत्येक मृतक के बदले कम से कम 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार एवं पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद प्लांट प्रबंधन द्वारा एफआईआर वापस लेने एवं बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल, 5 फरवरी को खरसिया थाना क्षेत्र के बानीपाथर स्थित मंगल कार्बन प्लांट में काम के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। फर्नेस को खोलते ही आग का तेज प्रेशर बाहर निकला और पास में काम कर रहे 8 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस प्लांट में पुराने टायर पिघलाकर काला तेल निकाला जाता है, जो रोड बनाने के काम आता है। आरोप है कि फर्नेस को ठंडा किए बिना खोला गया। मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी लापरवाही की वजह से यह भयावह हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलसे थे। सभी घायलों का इलाज रायपुर में चल रहा था। इलाज के दौरान 9 फरवरी को सबसे पहले 9 माह की मासूम बच्ची भूमि खड़िया ने दम तोड़ा।

अब उपचार के दौरान उसके पिता शिव खड़िया (27 वर्ष) समेत साहेब लाल खड़िया (45 वर्ष), इंदीवर (19 वर्ष) ने भी दम तोड़ दिया है। भूमि, शिव एवं साहेब लाल एक ही परिवार के सदस्य थे, पिता, पुत्र एवं 9 माह की मासूम बच्ची की मौत एक ही परिवार पर असहनीय आघात है। अन्य घायल मजदूरों का उपचार रायपुर स्थित Kalda Burns & Plastic Surgery Centre में जारी है, जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है।

इन गंभीर घायलों का चल रहा इलाज

उदाशिनी खड़िया (25 वर्ष) - 30-40 प्रतिशत झुलसी, कौशल (25 वर्ष) - 70-80 प्रतिशत झुलसे, प्रिया (32 वर्ष) -70-80 प्रतिशत झुलसी, घायल अब भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज दबाव के आरोप घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि प्लांट प्रबंधन द्वारा पीड़ित परिवारों पर एफआईआर वापस लेने और बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। इसके अलावा पर्याप्त मुआवजा देने समेत अन्य मांगें रखी गई है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी सहायता दी जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी/स्थायी नौकरी दी जाए। सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च प्लांट प्रबंधन से वसूला जाए। जिम्मेदार अधिकारियों व प्लांट प्रबंधन पर कठोर आपराधिक कार्रवाई की जाए।

बंदूक उठाने वाले हाथ चला रहे धड़ाधड़ सिलाई मशीन

■ सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति की मदद से, 40 सरेंडर माओवादियों का दल हिंसा छोड़ हुनर के रास्ते पर चल पड़ा है.

कांकेर। जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, आज उन हाथों से सिलाई मशीन धड़ाधड़ चल रही है। जिन हाथों ने बम और बारूद बनाए, आज वो हाथ शांति और सुकून का संदेश देने वाले ढोलक और हारमोनियम बजा रहे हैं। हिंसा और आतंक के रास्ते पर चलने वाले नक्सली, अब स्वरोजगार अपनाने की राह पर चल पड़े हैं। ये बदलाव शासन की नई नक्सल पुनर्वास नीति की बदौलत आया है।

कांकेर के भानुप्रतापुर ब्लॉक के चौगेल कैंप में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 40 सरेंडर माओवादी स्वरोजगार शुरू करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सली अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर समाज और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। शासन की योजना के तहत इनको हर संभव मदद मिल रही है। सरेंडर नक्सलियों को उनकी इच्छा मुताबिक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जा रहा है।

शासन की कोशिश है कि स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद ये पूर्व नक्सली अपना खुद का रोजगार शुरू कर नए जीवन की शुरूआत करें। ग्राम चौगेल के मुल्ला कैंप में 40 सरेंडर माओवादियों का दल हिंसा छोड़ जीवन जीने का हुनर सीखने के रास्ते पर चल पड़ा है। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करने वाले सरेंडर माओवादी इस बात से खुश हैं कि उनका पीछा हिंसा और बंदूक से छूटा। सालों से लाल आतंक के साए में हिंसा का दंश झेल रहा बस्तर संभाग अब तेजी से विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, हथियार उठाने वाले हाथ तेजी से हुनर सीखने के लिए जंगल छोड़ कैंप का रुख कर रहे हैं। शासन की ओर से भी उनको हर संभव आर्थिक मदद दी जा रही है। आत्मसमर्पित और पीड़ित नक्सल पुनर्वास नीति-2025 के अंतर्गत उनको सृजनात्मक और रोजगारमूलक गतिविधियों के तहत ट्रेंड किया जा रहा है। भानुप्रतापपुर विकासखंड से लगे ग्राम चौगेल (मुल्ला) का बीएसएफ कैम्प परिसर 'कौशलगढ़' बन गया है, जहां समाज की मुख्यधारा में लौटे सरेंडर माओवादियों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही उन्हें शिक्षित भी किया जा रहा है। कक्षा पहली से आठवीं तक के पाठ्यक्रमों का कोर्स इनको कराया जा रहा है। सरेंडर नक्सली भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ें। सरेंडर माओवादियों को 20 -20 के बैच में बांटकर हुनरमंद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फोन व्हीलर चलाने की ट्रेनिंग ले रहे आत्मसमर्पित माओवादी मनहेर तारम, उम्र 40 साल, ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे वे पूरी रूचि के साथ सीख रहे हैं। ट्रेनर द्वारा स्टेयरिंग थामने से लेकर क्लच, ब्रेक और एक्सिलरेटर का प्रयोग करना सिखाया जा रहा है।ड्राइविंग के अलावा सिलाई और काष्ठशिल्प का प्रशिक्षण कैम्प में दिया जा रहा है। सरेंडर माओवादी नरसिंह नेताम ने बताया कि वह भी फोर व्हीलर की ड्रायविंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं। यहां आकर ऐसी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं, जिससे आगे का जीवन बेहतर हो सके।

गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सील

नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर प्रशासन ने की कार्रवाई

मुंगेली। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन एवं चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद की गई। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ. कमलेश कुमार एवं नायब तहसीलदार हरीश यादव की संयुक्त टीम ने गर्ग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। डॉक्टर की अनुपस्थिति में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जो नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस समय भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे, जिस पर संबंधित संस्था को नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। सीएमएचओ ने कहा कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

छात्रों के बैग से 14 बाईबिल की पुस्तकें बरामद, व्याख्याता को नोटिस जारी

जशपुर। जशपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरसई में नियमों की अनदेखी कर छात्रों को बाइबिल बांटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय के एक व्याख्याता ने कक्षा में बाइबिल की प्रतियां वितरित की, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, 10 फरवरी को व्याख्याता दीपक तिग्गा विलंब से विद्यालय पहुंचे और बिना प्राचार्य को सूचित किए सीधे कक्षा में चले गए, जहां उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बाइबिल की पुस्तिकाएं वितरित की। मामला सामने आने के बाद छात्रों के बैग की जांच की गई, जिसमें बाइबिल की 14 प्रतियां बरामद होने की बात कही जा रही है।

प्राचार्य ने इसे गंभीर प्रशासनिक उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है।

साथ ही आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। फिलहाल प्रकरण की जांच की जा रही है। वहीं व्याख्याता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

मुर्गा चौक में भारत बंद के दौरान हंगामा, 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियनों का जोरदार प्रदर्शन

■ मजदूरों का आरोप है, नए कानून उनके अधिकारों को कमजोर करते हैं. कंपनी को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं.

दुर्ग। 4 नए लेबर कानूनों सहित विभिन्न श्रमिक मुद्दों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के तमाम यूनियनों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों का यह प्रदर्शन सुबह 5 बजे से ही शुरू हुआ। मुर्गा चौक पर बड़ी संख्या में यूनियन नेता और श्रमिक एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों को कुछ समय के लिए रोका गया, जिससे इलाके में हलचल का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन यूनियन नेताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा।

कुछ समय तक मुर्गा चौक पर पुलिस, बीएसपी अधिकारियों और हड़ताल में शामिल नेताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जहां यूनियन प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर डटे रहे।

मजदूर नेता विनोद कुमार सोनी ने कहा कि वर्षों पहले बनाए गए श्रम कानून मजदूरों, महिलाओं और कारखानों के हितों की रक्षा के लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन्हें खत्म कर चार नए लेबर कानून लागू किए हैं। मजदूर नेता का आरोप है कि इन कानूनों से ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार कमजोर हो जाएंगे और मजदूरों के पास अपनी बात रखने का मंच नहीं मिलेगा।

सीटू के पूर्व अध्यक्ष एस.पी. डे ने चार नए श्रमिक कानूनों को खतरनाक बताते हुए कहा, इससे मजदूरों को गुलाम जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनका दावा है कि 300 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में प्रबंधन की मनमानी बढ़ सकती है। सूटी के पूर्व अध्यक्ष ने 39 महीनों से लंबित एरियर और वेज रिवीजन को जल्द पूरा करने की मांग भी उठाई है।

मजदूर यूनियन के नेता अरुण कुमार सिसोदिया ने कहा, नए कानूनों के तहत काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जबकि उनकी सुरक्षा अब भी बड़ा सवाल है। मजदूर यूनियनों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में महापर्व महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू

धमतरी। बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। घराती-बाराती अब विवाह से पहले की रस्मों को पूरा करने में जुटे हैं। शहर के इतवारी बाजार स्थित सबसे प्राचीन श्री बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 11 से 15 फरवरी तक भगवान भोलेनाथ के विवाह को पूरे विधि-विधान के साथ किया जा रहा है। पहले दिन हल्दी की रस्मे निभाई गई। इस दौरान मंदिर को भव्य रूप से झालर लाइटों से सजाया गया है। रोजाना भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। हल्दी, मेहंदी, मंगल गीत के बाद भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने तैयारी कर ली है। श्री बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन पवार ने कहा, 8 दिन पूर्व मंदिर ट्रस्ट, बोलबम कांवरिया संघ के सदस्य और भक्तों के साथ बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में रूप रेखा तैयार की गई है। प्रतिवर्ष 5 दिनों तक शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है उस पर चर्चा हुई है। 11 फरवरी को हल्दी, 12 फरवरी को मेंहदी, 13 को मंगल गीत।

70 मवेशियों के साथ कर रहे थे बॉर्डर पार, तस्कर गिरफ्तार

जीपीएम। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट यानि पशु परिरक्षण अधिनियम के बावजूद मवेशियों की अवैध तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बड़ा मामला जीपीएम में सामने आया है। यहां मुंगेली जिले से 70 भैंसों को पैदल जंगल के रास्ते मध्य प्रदेश के अनूपपुर के लपटा ले जाया जा रहा था। मरवाही थाना क्षेत्र के साल्हेकोटा जंगल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मवेशियों को जब्त कर लिया। मवेशियों के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि जंगल के रास्ते से बड़ी संख्या में कुछ लोग मवेशियों को लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मरवाही थाना पुलिस की टीम देर रात मौके पर पहुंची। पुलिस ने मवेशियों को लेकर जा रहे लोगों से परिवहन संबंधी दस्तावेज, डाक्टरी परीक्षण प्रमाण पत्र, रूट चार्ट एवं कलेक्टर की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई वैध दस्तावेज मवेशियों के साथ जा रहे लोग नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि लोरमी (जिला मुंगेली) से लपटा की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है।

छत्तीसगढ़ का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन धमतरी में बनेगा

धमतरी। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गंगरेल जलाशय के बीच बने आइलैंड को पर्यटन के लिए सजाया संवारा जाने लगा है। धमतरी कलेक्टर ने गंगरेल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संचालित विभिन्न विकास कार्यों और ठेमली आइलैंड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर अधिकारियों के साथ पैदल चलकर पाथवे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर ने व्यू प्वाइंट और वाच टावर कहां बनाए जाएंगे इसको लेकर जगह का सिलेक्शन किया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने ठेमली आइलैंड में किये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों की भी जानकारी अफसरों से ली। निरीक्षण के दौरान डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव, जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह ठाकुर, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटन विकास से स्थानीय युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों एवं ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

शासकीय कॉलोनी में गहराया जल संकट, लोग हो रहे परेशान

कोरिया। जिला मुख्यालय कलेक्टर बंगला से सटी शासकीय कॉलोनी में इन दिनों गंभीर जल संकट है।बीते चार दिनों से लोगों के घरों में नलों से पानी नहीं आया। पानी की कमी के कारण कर्मचारियों और उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि विभागीय लापरवाही और अस्थायी मरम्मत के कारण बार-बार सामने आ रही है। कॉलोनी में लगे पानी पंप की स्थिति लंबे समय से खराब है। पानी सप्लाई की मोटर पिछले 20 से 25 दिनों से बार-बार खराब हो रही है। बीच में करीब 8 दिनों तक मोटर पूरी तरह बंद रही। शिकायतों के बाद उसे बनवाया गया, लेकिन मरम्मत के बाद वह केवल 4 दिन ही चल सकी और फिर से ठप हो गई।लोगों का आरोप है कि हर बार मोटर अस्थायी रूप से ठीक कर दी जाती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता।

बिना अनुमति रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में किया था प्रदर्शन

दुर्ग। दुर्ग के पटेल चौक पर रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता और प्रॉपर्टी डीलर मनोज राजपूत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस पांच अन्य आरोपियों को पकड़ चुकी है, जबकि कई आरोपी अब भी फरार हैं। दुर्ग में सिटी कोतवाली पुलिस ने फिल्म अभिनेता और बिल्डर को बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पहले ही पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल, पूरा मामला एक दिसंबर 2025 का है। पटेल चौक पर रजिस्ट्री शुल्क के विरोध में छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता और प्रॉपर्टी डीलर मनोज राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी डीलर और किसान बिना अनुमति के बीएसएनएल कार्यालय के पास सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस की समझाइश के बाद भी वे प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पानी के पाउच फेंका जा रहा था।

यूजीसी के समानता विनियम 2026 पर मुंगेली से उठा मजबूत समर्थन

एसटीएसी ओबीसी एकता महासंघ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा समर्थन पत्र

मुंगेली। उच्च शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जीसी) द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 को मुंगेली जिले में व्यापक समर्थन मिला है। एससीएसटी, ओबीसी एकता महासंघ, जिला मुंगेली ने इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री एवं यूजीसी चेयरमैन को समर्थन पत्र प्रेषित कर इन विनियमों का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। महासंघ ने अपने पत्र में कहा है कि ये विनियम देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निष्पक्ष, सुरक्षित और समावेशी शैक्षणिक वातावरण स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। लंबे समय से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं अन्य वंचित समुदायों के छात्रों को शैक्षणिक परिसरों में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसे में

यूजीसी द्वारा लाए गए ये नियम न केवल भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, बल्कि उसके निवारण के लिए ठोस संस्थागत व्यवस्था भी सुनिश्चित करते हैं।नए विनियमों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक मार्गदर्शन, परामर्श, करियर सलाह, छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी तथा उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। महासंघ का कहना है कि यह केंद्र उन छात्रों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा, जो स्वयं को उपेक्षित या अलग-थलग महसूस करते हैं। विनियमों के अनुसार हर संस्थान में एक समानता समिति गठित की जाएगी, जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए जिम्मेदार होगी। समिति में एससी, एसटी, ओबीसी दिव्यांगजन और महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेगा, ताकि निर्णय प्रक्रिया में विविध समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। शिकायतों का गोपनीय पंजीकरण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इन नियमों में 24X7 समानता हेल्पलाइन, मोबाइल 'समानता दल' और विभागीय स्तर पर 'समानता दूत' जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इन माध्यमों से छात्रों और कर्मचारियों को त्वरित सहायता और शिकायत दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। साथ ही, संस्थानों को अपनी समानता संबंधी गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी। एक राष्ट्रीय निगरानी समिति इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। महासंघ ने विशेष रूप से इस बात का स्वागत किया है कि विनियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। यूजीसी ऐसे संस्थानों की वित्तीय सहायता रोक सकता है, डिग्री प्रदान करने का अधिकार समाप्त कर सकता है या उनकी मान्यता रद्द कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये नियम केवल कागज़ी न रहकर जमीनी स्तर पर लागू हों। महासंघ ने कहा कि ये विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप हैं, जो शिक्षा में समावेशन, समान अवसर और सामाजिक न्याय पर जोर देती है। संगठन ने विश्वास जताया कि यदि इन नियमों का ईमानदारी से पालन किया गया तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, सम्मान और गरिमा की नई संस्कृति विकसित होगी।

बकाया कर नहीं देने पर परिवहन विभाग की कार्रवाई

जशपुर। जिले में परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से कर और पैनल्टी बकाया होने के कारण विभाग ने जिले की पांच बड़ी बसों को जब्त कर लिया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बकाया राशि एक सप्ताह के भीतर जमा नहीं होने पर इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।

विभाग का कहना है कि नियमों के अनुसार कर, पैनल्टी या ब्याज का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों को कुर्क कर नीलामी के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाएगी। परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और जो भी वाहन बिना वैध कर भुगतान के सड़कों पर पाए जाएंगे, उन पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। निर्धारित अवधि के भीतर कर जमा न करने की स्थिति में कानूनी प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

पीएम सूर्य घर योजनाः सिलफिली के मनोज बने दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत

रायपुर। प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुफ्त

बिजली योजना के तहत् राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तेजी के साथ जगमग हो रही है। सूरजपुर जिले के सिलफिली निवासी श्री मनोज विश्वास योजना के सफल लाभार्थी बनकर दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। श्री विश्वास ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कर न केवल बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत की है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सूरजपुर जिले में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जो आमजन की बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में 25 सक्रिय वेंडर कार्यरत हैं, जिससे आवेदन से लेकर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो रही है। हितग्राही श्री मनोज विश्वास की सफलता से प्रेरित होकर अन्य नागरिक भी इस योजना से जुड़ रहे हैं। यह योजना आर्थिक राहत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी जन आंदोलन बनती जा रही है।

अवैध गुटखा भंडारण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख का माल जब्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध रूप से गुटखा भंडारण पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खमतराई क्षेत्र में की गई छापामार कार्रवाई में 160 बोरी सितार गुटखा और 300 बोरी तंबाखू जब्त किया गया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। राजधानी में इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, खमतराई इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से गुटखा का भंडारण किया जा रहा था। दामों में बढ़ोतरी के बीच कालाबाजारी की आशंका पर पुलिस ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से 160 बोरी सितार गुटखा और 300 बोरी तंबाखू बरामद की गई। यह पूरी कार्रवाई रायपुर नार्थ के डीसीपी मयंक गुर्जर के नेतृत्व में की गई। स्थानीय पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पेशी के दौरान कोर्ट परिसर से भागे दो आरोपी

रायपुर। रायपुर कोर्ट में पेशी के दौरान मोहर्रिर की अभिरक्षा से दो आरोपियों के भागने का मामला सामने आया है। दोनों ही आरोपी हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं से जुड़े मामले में विचाराधीन थे। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां पेशी के लिए लाए गए राजेश मारकण्डेय और तुलाराम मारकण्डेय मोहर्रिर की अभिरक्षा से भागने में कामयाब हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोर्ट परिसर में हलचल मच गई। मिली सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

23 फरवरी को होगी सेना पुलिस भर्ती रैली

रायपुर। इंडियन आर्मी 23 फरवरी को पुलिस ग्राउंड, झिंझरी (कटनी, मध्य प्रदेश) में महिला मिलिट्री पुलिस पद के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली करेगी। यह रिक्रूटमेंट रैली आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, रायपुर (छत्तीसगढ़) के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी 33 जिलों की योग्य महिला उम्मीदवारों के लिए खुली होगी। यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन महिला कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 30 जून, 2025 और 10 जुलाई, 2025 के बीच इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को सफलतापूर्वक पास किया है। केवल ऑनलाइन एग्जाम सफलतापूर्वक पास करने वाले कैंडिडेट्स को ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफलतापूर्वक पास होने वाले कैंडिडेट्स का 24 फरवरी को आर्मी हॉस्पिटल, जबलपुर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। केवल वे ही अगले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे जो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे।

विश्व रेडियो दिवस 2026 का आयोजन 13 फरवरी को रायपुर में

रायपुर। प्रसार भारती एवं यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में 13 फरवरी 2026 को विश्व रेडियो दिवस का भव्य आयोजन रायपुर में किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महत्व का यह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और आकाशवाणी महानिदेशालय के सहयोग से आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ यूनेस्को के प्रतिनिधि, प्रसार भारती एवं आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। वर्ष 2026 के विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्धारित की गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के 'ऑफर' वाले बयान पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार, सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं ऐसा बयान

भूपेश की न तो छत्तीसगढ़ को जरूरत है, और न ही भाजपा को

रायपुर। भूपेश बघेल के बीजेपी में शामिल होने के ऑफर पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी जरूरत न छत्तीसगढ़ को है, और न ही भाजपा को है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं।

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने गुरुवार को अपने विभाग का लेखा-जोखा मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का दवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों का जवाब भी दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के पीडीएस दुकान के खाली होने के आरोप पर कहा कि जिन लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, जिनके ऊपर केस चल रहा हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी पीडीएस की दुकानें खाली हो गई हैं। जिन लोगों ने खाली किया आज वे विपक्ष में हैं।

वहीं अमरजीत भगत के नक्सली कमांडर हिडमा को सपोर्ट वाले बयान पर कहा मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है। झीरम घाटी के नाम पर ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इस बात को साबित करता है कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या यहाँ के लोग हों। ये कहते हैं कि झीरम के सबूत इनके पास है। जब सबूत है तो स्वाभाविक

है, आपसी गुटबाजी के कारण झीरम कांड हुआ है।

दरअसल, कांग्रेस पार्टी को इस बात का दुख है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, और कांग्रेस के समर्थक खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने हमेशा मंचों से कहा है कि वे नक्सलियों के साथ खड़े हैं।

वहीं बीजापुर विधायक के सुरक्षा वाले मामले में केदार कश्यप ने कहा कि कहीं किसी को जाने के लिए नहीं रोका जा रहा है। वो बिना सुरक्षा के अंदरूनी क्षेत्र में चले जाते थे। उनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। वो बिना सुरक्षा और बिना पुलिसकर्मी के नक्सल क्षेत्र में घूमते थे, उन्हें क्या सुरक्षा की आवश्यकता है। अब बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है।

असम में कांग्रेस नेता चुनाव में गए हैं, क्या बीजेपी नेता भी जाएंगे? इस पर केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि असम में हमारे नेता प्रचार करने जा रहे है। फिर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में लोग किसलिए जा रहे, ये बाद में पता चलेगा। पिछले बार तो यहां लाकर बकरा और सूअर खिलाए थे। इस बार क्या खिलाएंगे ये देखना होगा।

वहीं बस्तर में स्वास्थ्य की स्थिति पर मंत्री कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार में 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसे लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में और भी विस्तार हो रहा है। अंदुरूनी क्षेत्र में भी चिकित्सा का जाल बिछ रहा है। वहीं युवा कांग्रेस की महापंचायत का केदार कश्यप ने स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि वो वास्तविक लोगों को लेकर आएंगे, मरे हुए लोगों को न लाए।

बताया विभाग का लेखा-जोखा

2 सालों में परिवहन विभाग के कार्यों को लेकर कहा कि सीएम ग्रामीण बस योजना से लोगों को लाभ मिला। 425 नए गांव तक पहली बार बस पहुंचे। सड़क दुर्घटना में रायपुर जिले को सड़क दुर्घटना में शून्य मृत्यु जिले के रूप में शामिल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1 लाख रुपए छूट दी जा रही है। आटो एक्सपो के माध्यम से 133.4 करोड़ के आरटीओ टैक्स का छूट मिला।

बस संगवारी एप की सुविधा लोगों को दी गई है। वाहन 4.0 और सारथी 4.0 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से हो रहे है। आरसी/डीएल की घर पहुंच सेवा के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र को डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। ई-चालान के माध्यम से अनफिट वाहनों पर कार्रवाई हो रही है। वर्तमान में 20 टोल नाकों से गुजरने वाले बिना फिटनेस और टैक्स के वाहनों पर ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायलों को कैशलेश उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

वन विभाग की दो साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 355 हाथियों का विचरण हो रहा है। हाथी-मानव द्वंद कम हो, इस पर काम हो रहा है। प्रभावित इलाकों में एलिफेंट ट्रेकिंग मेसेज के माध्यम से जानकारी दी जाती है। दो सालों में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान रचा है। सघन वनों में 70% घनत्व बढ़ा है। 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। भूमि स्वामी को वृक्षारोपण के लिए योजना बनाकर प्रेरित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले देवगुड़ियों का निर्माण कराया गया। 463 पदों में भर्ती की गई, 1500 में और भी करना है। वर्तमान में बाघों की संख्या 35 है। बाघों के संरक्षण में काम किया जा रहा है। वन भैंसा, पहाड़ी मैना के संरक्षण में काम किया जा रहा है। वहीं सहकारिता विभाग में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प से विभाग लोगों के हित में काम कर रहा है। 515 नई पैक्स समितियों का गठन किया गया है। 2739 उपार्जन केंद्रों में 25.49 किसानों से 139 मिट्रिक टन धान खरीदी हुई है, 1.45 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया। उच्च शक्कर कारखाने लगाए गए है।

छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारियों पर आईटी की रेड

■ बिलासपुर से जांजगीर तक हड़कंप

बिलासपुर/ जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड से हड़कंप मच गया है। यह छापा बिलासपुर और जांजगीर चांपा में पड़ा है। यहां के कोयला कारोबारियों पर यह रेड पड़ी है। अभी इस रेड को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों जिले में छापे की कार्रवाई चल रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एसआईआर की स्टीकर लगी गाड़ियों में टीम पहुंची है और बिलासपुर में यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर में आईटी विभाग ने कोल कारोबार से जुड़े फिल ग्रुप के कई जगहों पर हुए छापेमार कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग जगहों पर एक साथ धावा बोला है। टीम ने ऑफिस और फैक्ट्री सहित कई इलाकों में रेड मारा है। आयकर विभाग की टीम ने बिलासपुर में सिविल लाइन, सिरगिट्टी और तारबहार इलाके में छापा मारा है। कोयला

कारोबारी और फिल ग्रुप के मालिक प्रवीण झा के ठिकानों पर यह रेड की कार्रवाई चल रही है।

आयकर विभाग की टीम बाकायदा एसआईआर सर्वे वाली गाड़ियों में पहुंची है। उनके वाहनों पर एसआईआर के स्टीकर लगे हुए हैं। इस छापेमार कार्रवाई को गोपनीय रखने का प्रयास किया गया है। बताया जा रहा है कि फिल ग्रुप के मालिक प्रवीण झा के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित दफ्तर और रामा वर्ल्ड स्थित घर पर रेड की कार्रवाई हुई है। टीम दस्तावेजों सहित वित्तीय लेनदेन और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस छापे को लेकर अभी आयकर विभाग की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

छत्तीसगढ़ की 4 सेंट्रल जेलों को मिला आईएसओ 9001:2015 सर्टिफिकेट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जेल प्रशासन को गुणवत्ता और सुधारात्मक न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य की चार केंद्रीय जेलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001:2015 का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह पहल जेलों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं जेल विभाग के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर जेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से आईएसओ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

प्रमाणन जारी करने वाली संस्था द्वारा 11 फरवरी 2026 को केंद्रीय जेल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर के जेल अधीक्षकों को आईएसओ 9001:2015 के प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

इस प्रमाणन के माध्यम से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रियाओं में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी। साथ ही बंदी कल्याण, मानवाधिकार संरक्षण, जोखिम प्रबंधन और जन विश्वास में भी वृद्धि होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह पहल सुधारात्मक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी।

आईएसओ प्रमाणन की इस पूरी प्रक्रिया में योगेश सिंह क्षत्री (जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल रायपुर), खोमेश मंडावी (जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल बिलासपुर), मनीष संभवकर (जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल दुर्ग), अक्षय सिंह राजपूत सहित रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर केंद्रीय जेलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़

राज्य में 10,796 हेक्टेयर क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती

रायपुर। खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 10,796 हेक्टयर क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती हो रही है। जिसमें 7,315 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जिला प्रशासन भी ऑयल पाम के लिए जमीन चिहांकित कर रकबा बढ़ाने प्रयासरत हैं।

इसी क्रम में संचालक उद्यानिकी श्री लोकेश कुमार ने दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों के किसानों के खेतों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया।

उद्यानिकी संचालक श्री लोकेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन, समेकित उद्यानिकी विकास कार्यक्रम तथा नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया।

गौरतलब है कि राज्य में ऑयल पाम की खेती वर्ष 2012-13 से की जा रही है।

वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में लगभग 10,796 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया जा चुका है, जिससे 7,315 किसान लाभान्वित हुए हैं। अब तक लगभग 1,394.88 टन फ्रेश फ्रूट बंच का उत्पादन हुआ है। भारत सरकार द्वारा फ्रेश फ्रूट बंच का न्यूनतम मूल्य 16,460.46 रुपये प्रति टन निर्धारित कया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों से 22,000 रुपये प्रति टन की दर से सीधी खरीदी की जा रही है।

संचालक श्री लोकेश कुमार ने दुर्ग जिले के ग्राम ढाबा में श्रीमती सुनिती देवी मढरिया के एक हेक्टेयर में लगाए गए ऑयल पाम के साथ टमाटर की अंतरवर्ती फसल तथा श्री प्रवीण मढरिया के एक हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम के साथ केले की खेती का अवलोकन किया। यहां किसानों से सब्सिडी और अनुदान से जुड़ी जानकारी साझा की। इसके पश्चात दुर्ग जिले के ही परसदापार, चिखला एवं राजपुर तथा बेमेतरा जिले के डोंगीतराई गांव में चयनित और लाभान्वित किसानों के खेतों में रोपित ऑयल पाम, केला, आम, फेंसिंग और अंतरवर्ती फसलों का अवलोकन किया।

संचालक श्री लोकेश कुमार ने किसानों को योजना के अंतर्गत ऑयल पाम पौध, फेंसिंग, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई तथा अंतरवर्ती फसलों पर मिलने वाली आर्थिक सहायता और उत्पाद की बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑयल पाम की खेती किसानों की आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन रही है। राजपुर स्थित शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र में प्लग टाइप सीडलिंग यूनिट का निरीक्षण कर इसे शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि आगामी मौसम में किसानों को गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध कराई जा सके।

आरटीई: रायपुर में 828 स्कूलों में दिए जाएंगे प्रवेश

रायपुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के प्रवेश के लिए अधिकारिक प्रक्रिया जारी है। जल्द ही आरटीई के तहत प्रवेश भी शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार प्रवेश में छात्रों की संख्या काफी कम होगी। रायपुर में कुल 828 स्कूल में प्रवेश दिए जाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य जारी है। इसमें अभी तक 826 स्कूलों का सत्यापन हो चुका है। जिसमें 3072 छात्र-छात्राएं हैं। अभी दो स्कूल बाकी है। जिन्हें जोड़ा जाए तो मुश्किल से आंकड़ा 3100 तक जाएगा। पिछले साल आरटीई के तहत रायपुर जिले में लगभग 4653 सीटों पर प्रवेश हुआ था। सत्र 2025-26 तक नर्सरी और केजी में भी आरटीई के तहत प्रवेश दिया गया था। आरटीई छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में उपलब्ध डाटा के अनुसार, सत्र 2025-26 के अनुसार केजी 1, नर्सरी और पहली कक्षा में कुल 53023 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया था। जिसमें पहली कक्षा में

लगभग 10500 बच्चों को प्रवेश मिला। यह लगभग 19.80 फीसदी है। आरटीई के तहत 42 हजार 600 से ज्यादा बच्चों का प्रवेश नर्सरी और केजी में हुआ था।

आरटीई के तहत अभी नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन का काम जारी है। छात्र पंजीयन 16 फरवरी से 31 मार्च तक होगा। 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लॉटरी एवं आबंटन होगा। जिसके बाद छात्रों को 1 मई से 30 मई तक प्रवेश लेने होंगे। द्वितीय चरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। जिसमें नए स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 1 जुलाई से 11 जुलाई तक छात्र पंजीयन होंगे। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉटरी एवं आबंटन होगा। जिसके बाद छात्रों को 3 अगस्त से 17 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

सिक्किम से अध्ययन भ्रमण पर आए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित धरा को सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही हमारी सरकार : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है और धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित इस धरा को हमारी सरकार सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में सिक्किम राज्य से अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे पत्रकारों के दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया और उनसे छत्तीसगढ़ को लेकर ढेर सारी बातें साझा की। उन्होंने सभी अतिथियों को राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता और आतिथ्य पाकर सभी पत्रकार अभिभूत हुए और उन्हें सिक्किम आने का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है तथा यहां 31 प्रतिशत आदिवासी समुदाय निवासरत है। वनोपज संग्रहण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। जशपुर जिले में स्व-सहायता समूह की महिलाएं जशप्योर ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद तैयार कर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए सरकार द्वारा 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से

भुगतान किया जा रहा है तथा चरण पादुका योजना के तहत निःशुल्क चप्पल प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही छह हजार से अधिक जोड़े इस योजना के अंतर्गत विवाह बंधन में बंधे, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नवदंपतियों को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं 15 हजार रुपये का सामग्री सहयोग प्रदान किया जाता है।

नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सफल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। राज्य सरकार की आकर्षक पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50 हजार रुपये की सहायता तथा तीन वर्षों तक प्रति माह 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 2,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार से जोडने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा बस्तर पंडुम कैफे का सफल संचालन इसका सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत 17 शासकीय योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है, जिससे सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा से तेजी से जुड़ रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चित्रकोट जलप्रपात, कुटुम्बसर गुफाएं, अबूझमाड़ के वन और धुड़मारास जैसे स्थल प्रदेश की पहचान हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होम स्टे को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को पांच कमरों तक निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं औद्योगिक विकास के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां निम्न आय वर्ग के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने प्रदेश की आकर्षक नवीन औद्योगिक नीति का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना से प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम की पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मेक इन इंडिया का प्रभावी स्वरूप देखने को मिला। भिलाई स्टील प्लांट में रेल पटरियों सहित विभिन्न इस्पात उत्पादों का निर्माण प्रदेश के औद्योगिक सामर्थ्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इकाइयों को हमें करीब से देखने का मौका मिला और हम जान पाए है कि इस प्रदेश का देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है।

दक्षिण एशिया में भारत की चुनौती

केएस तोमर

भारत अपने पड़ोस में यदि अकेला पड़ गया है, तो यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह दशकों पुरानी कूटनीतिक लापरवाही, रणनीतिक रूप से कम प्रतिक्रिया व राजनीतिक इरादों को ठोस नतीजों में बदलने में लगातार नाकामी का मिला-जुला नतीजा है। नई दिल्ली क्षेत्रीय नेतृत्व की ख्वाहिश रखती है, पर वह सद्भावना को स्थायी प्रभाव में बदलने में हिचकिचाती रही है, जिससे चीन को रणनीतिक शून्य को भरने का मौका मिल गया है। भारत ने उस जगह को छोड़ दिया है, जिसे कभी उसका निर्विवाद प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। विदेश नीति के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का लेन-देन वाला रवैया, जिसमें अचानक बदलाव, चुनिंदा जुड़ाव और अल्पकालिक फायदे को प्राथमिकता देना शामिल है, ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय समीकरणों को बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान के साथ सामरिक बातचीत फिर से शुरू करने की ट्रंप की नई इच्छा (जो आतंकवाद विरोधी नजरिये, अफगान संकट के असर या कूटनीतिक सौदेबाजी से प्रेरित है) आतंकवाद के मुद्दे पर इस्लामाबाद को कूटनीतिक तौर पर अलग-थलग करने की भारत की कोशिशों को कमजोर करती है। इस अस्पष्टता के साथ ही बहुपक्षीय फ्रेमवर्क के प्रति ट्रंप की कम होती प्रतिबद्धता और चीन पर लगातार बदलते रुखों ने छोटे दक्षिण एशियाई देशों को प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच ज्यादा आक्रामक तरीके से संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसे-जैसे वाशिंगटन का क्षेत्रीय रुख बदलता है, भारत का अपने आस-पड़ोस में नेतृत्व का दायरा सिकुड़ता जाता है, जिससे नई दिल्ली को उस बढ़ी हुई अनिश्चितता को प्रबंधित करना पड़ता है, जो इस क्षेत्र से बहुत दूर से आने वाली नीति की वजह से पैदा होती है। भारत को तुरंत वास्तविकता, विनम्रता और लगातार बातचीत पर आधारित सुधार की जरूरत है। पहला कदम है उच्च-स्तरीय राजनीतिक वार्ता। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ढाका, कोलंबो, काठमांडो, नेप्यीडॉ और माले जैसी राजधानियों की यात्राएं फिर से एक खास इरादे के साथ शुरू होनी चाहिए। घरेलू राजनीति में कथित पक्षपात की जगह राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। दूसरा, लंबित कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। तीस्ता समझौता, नेपाल व भूटान के साथ क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी और म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर को कूटनीति से आगे बढ़ाना होगा। भारत को चीन के कर्ज पर आधारित मॉडल से खुद को अलग दिखाने के लिए, ऋण के बजाय अनुदान पर आधारित एक दक्षिण एशियाई आर्थिक सहायता कोष बनाना चाहिए। तीसरा, सैन्य कूटनीति को फिर से शुरू करना चाहिए-संयुक्त अभ्यास, अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और सस्ते रक्षा हथियारों की आपूर्ति को चीनी हथियारों के विकल्प के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। भारत को भरोसेमंद रक्षा भागीदार के तौर पर अपनी पहचान फिर से बनानी चाहिए, खासकर श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के लिए। चौथा, भारत को सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल में जान डालनी चाहिए। क्वाड व जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ मिलकर, भारत बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और समुद्र के नीचे पारदर्शी व समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकता है। पांचवां, छात्रवृत्ति, यूथ एक्सचेंज, बॉलीवुड, योग और क्रिकेट कूटनीति के जरिये सांस्कृतिक कूटनीति को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। विश्वास और सद्भावना को बहाल करने के लिए भारत को सिविल सोसाइटी व छात्रों से फिर से जुड़ना चाहिए। छठा, भारत को बहुपक्षीय और मीडिया मंचों पर अपनी बात रखने की जगह वापस पानी होगी। भारत को एफएटीएफ से लेकर ब्रिक्स व बिम्सटेक तक, कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान के आतंकी जुड़ाव को दुनिया के सामने लाना चाहिए। एक नई मीडिया रणनीति के तहत चीन-पाकिस्तान के दुष्प्रचार का त्वरित मुकाबला करना चाहिए, जिसमें स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री, क्षेत्रीय इन्फ्लुएंसर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए फंडिंग शामिल हो। सातवां, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़कों आदि) में निवेश बहुत जरूरी है।

बंगाल में एसआईआर विवाद से गरमाई सियासत

आरती आर जेरथ

राजनीति में दिखना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार अपनी सरकार बनाए रखने की बड़ी लड़ाई में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अचानक पेश होकर बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती दी।

23 साल के अंतराल के बाद वकील की काली वर्दी पहनकर (वह एक योग्य वकील भी हैं), उन्होंने एक याचिकाकर्ता के तौर पर अपना केस खुद लड़ा और प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ को अपनी शानदार कानूनी दलीलों से प्रभावित किया। उन्होंने यह कहकर एक राजनीतिक संदेश भी दिया कि निर्वाचन आयोग भाजपा के कहने पर यह काम कर रहा है। पीठ ने उनकी बात सम्मान के साथ सुनी। शायद न्यायाधीश इस बात से हैरान थे कि एक मुख्यमंत्री अपना केस खुद लड़ने के लिए अदालत में पेश हुईं। ममता बनर्जी ऐसा करने वाली पहली मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करते समय सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए, लेकिन उसने ममता बनर्जी की इच्छा के मुताबिक इस पर रोक लगाने से मना कर दिया।

असल में, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। भले ही ममता ने कानूनी लड़ाई नहीं जीती हो, पर उन्होंने इस दिखावे की लड़ाई में इतनी प्रशंसा पा ली कि भाजपा कुछ देर के लिए चुप हो जाए। उनके मुख्य विरोधी को समझ नहीं आ रहा कि

उस नेता को कैसे जवाब दें, जिसने विधानसभा चुनाव को बंगाल की खास पहचान को 'बाहरी दल', जैसा कि वह भाजपा को कहती हैं, के हमले से बचाने के अपने व्यक्तिगत अभियान के तौर पर दिखाकर माहौल बिगाड़ दिया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने निजी तौर पर माना कि ममता बनर्जी की 'फाइटिंग स्पिरिट' का मुकाबला करना मुश्किल है, जो 34 साल तक पश्चिम बंगाल पर राज करने वाले वाम मोर्चे की ताकत के खिलाफ वर्षों तक सड़क पर लड़ाई लड़कर और भी बेहतर हुई है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़कर अपने नाटकीय कदम से मतदाताओं को कई स्पष्ट संदेश दिए हैं।

पहला, एसआईआर में गड़बड़ियां भरी हुई हैं, जिन्हें मतदाताओं को शामिल करने के बजाय हटाने के लिए बनाया गया है। दूसरा, पश्चिम बंगाल को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पड़ोसी भाजपा शासित असम, जहां उसी समय चुनाव होने हैं, को एसआईआर प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तीसरा, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने अपना साहस नहीं खोया है और अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, चाहे सड़कों पर हो या देश की सबसे बड़ी अदालत में, अपने हर हथियार से लड़ेंगी, जिनके बारे में उनका दावा है कि एसआईआर की वजह से उन्हें बेवजह जुल्म और मानसिक तकलीफ हो रही है। यह ममता की उत्कृष्ट रणनीति है- भावनात्मक, अडिग, हमेशा सावधान रहने वाली, जो आम लोगों की तरफ से बड़े व ताकतवर लोगों से भिड़ने से भी नहीं हिचकिचाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपना केस नहीं जीतीं। सुप्रीम कोर्ट में अपने चालाकी भरे काम से वह जो संकेत देना चाहती थीं, उन्हें जमीन पर काम करने वाले लोगों ने समझ और पढ़ लिया है। जैसे कि भाजपा ममता बनर्जी के हाई-वोल्टेज भावनात्मक भाषण का जवाब देने के लिए फिर से तैयार हो रही है, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक उनके धमाकेदार अभियान को सिर्फ दिखावा नहीं समझना चाहिए, जिसके लिए वह मशहूर हैं। इसके पीछे तृणमूल में गहरी चिंता है कि मतदाता पुनरीक्षण की यह कवायद उसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है और भाजपा को फायदा पहुंचा सकती है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और यह काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा, नामों की वर्तनी और दूसरी जानकारियों में थोड़ी-सी गड़बड़ी की वजह से हजारों मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग के मुताबिक तार्किक विसंगतियों की सूची में डाल दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है, जहां ऐसी सूची बनाई गई है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का काम है। तृणमूल नेताओं का दावा है कि माइक्रो ऑब्जर्वर का पद एसआईआर प्रक्रिया के बीच में लाया गया था, ताकि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को दरकिनार किया जा सके, जिन्हें निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य सरकार के कहने पर धमकाया और काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तृणमूल नेताओं का यह भी दावा है कि मुस्लिम इलाकों व महिला मतदाताओं को माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए चुना जा रहा है, जिससे अक्सर उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। ये दोनों समूह ममता बनर्जी के मुख्य समर्थक हैं और मतदाता सूची में उनकी संख्या में कोई भी कमी नतीजे पर असर डाल सकती है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अच्छी तरह जानती हैं कि तीन कार्यकाल तक शासन में रहने के बाद, उनके खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी रूझान है। यह पांच साल पहले, 2021 में भी था। लेकिन भाजपा की बेवजह की गलतियों और एक रैली में पैर टूटने के बाद व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी के भावनात्मक प्रचार ने तृणमूल कांग्रेस को बचा लिया। वह पहले से भी ज्यादा मजबूती से सत्ता में वापस आईं, 294 विधानसभा सीटों में से 213 सीटें जीतीं और 48 फीसदी का भारी वोट शेयर हासिल किया।

एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग व भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की लड़ाई और भी तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी दुश्मन से लड़ने की कला में माहिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने पिछले नवंबर में पड़ोसी राज्य बिहार में राजग की शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी को चुनौती दी थी। पर, जैसा कि पश्चिम बंगाल का हर मतदाता जानता है, विधानसभा चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए है। मतदाताओं के साथ ममता बनर्जी के मजबूत भावनात्मक रिश्ते को चुनौती देने के लिए एक मजबूत स्थानीय नेता की कमी भाजपा की कमजोरी साबित हो सकती है। जैसा कि ममता बनर्जी ने 2021 में अपने हाथों में फुटबॉल पकड़कर कहा था, 'खेला होबे।' खेल पूरी तरह से शुरू हो गया है और यह दिखावे और जमीनी स्तर की रणनीति का एक दिलचस्प मुकाबला साबित हो रहा है।

एकात्मता के स्वर

दधीचि

ऋषि अथर्वण की सहधर्मचारिणी शांति से तीन पुत्र पैदा हुए। घृतव्रत, दधीचि और अथर्वशिर। परम्परा के अनुसार बड़े होने पर उपनयन संस्कार कर पढाई हेतु गुरुकुल में भेज दिया। भक्ति द्वारा गुरु का मन जीत कर सभी वेदों का अध्ययन कर लिया। वेदज्ञान के पश्चात् कठोर तपस्या की। इन्द्रदेव ने प्रकट हो अभिलाषा पूछी तब दधीचि ने कहा, मैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इन्द्र ने ब्रह्मज्ञान यह कहते हुए दिया कि यदि तुमने यह किसी और को बताया तो तुम्हारा सिर काट दिया जायेगा। ब्रह्मज्ञानी ऋषि ने सरस्वती नदी के किनारे आश्रम बनाकर प्रीतिथेई नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह आश्रम पर गुरुकुल परम्परा से छात्रों को ज्ञान देने लगे। एक बार दो व्यक्ति जो समान दिखाई देते थे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिये आश्रम पर आये। ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा वचन अनुसार मेरा सिर काट दिया जावेगा, इसलिये विद्या देने में चाह कर भी असमर्थ हूँ। तब जिज्ञासु दोनों बन्धुओं ने कहा यदि ऐसा है तो हम भी देख लेंगे। कृपया आप हमें स्वीकृति तो दें, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपका कटा सिर पुन: जोड़कर जीवित कर देंगे। जब दधीचि ने वास्तविक परिचय पूछा तो उन्होंने कहा हम सूर्यपुत्र जुड़वा देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों ने मनुष्य सिर के स्थान पर घोड़ों का सिर लगाकर ब्रह्मज्ञान की विद्या प्राप्त कर ली। देवेन्द्र ने क्रोधित हो तलवार द्वारा ऋषि दधीचि का सिर काट दिया। परन्तु अश्विनी कुमारों ने सुरक्षित रखे उनके सिर को पुन: जोड़कर जीवित कर दिया। यह सुसमाचार चारों और फैलने से ऋषि की कीर्ति और बढ़ गयी। एक समय युद्ध जीतने के बाद देवता लोग अपने शस्त्र लेकर दधीचि के पास पहुँचे निवेदन किया कि आप हमारे शस्त्र आश्रम पर रख लीजिये जब आवश्यकता होगी हम ले जायेंगे। देवता शस्त्र रखकर चले गये। जब अनेक वर्षों तक देवता शस्त्र लेने नहीं आये तब ऋषि ने अध्यात्म मंत्र-शक्ति के द्वारा सभी शस्त्रों को घोल बनाकर पी लिया। उसके भी अनेक वर्षों बाद देवताओं ने आकर ऋषि से अपने शस्त्र मोंगे तब ऋषि ने कहा आप अनेक वर्षों तक नहीं आये तो हम उन्हें मंत्र शक्ति द्वारा गलाकर पी गये हैं। वे हमारी रीढ़ की हड्डी में समाहित हो गये हैं। देवताओं में लकड़ी (बढ़ई) का काम करने वाले त्वष्टा नामक देवता के विश्वरूप नामक बालक हुआ जो वेदों में पारंगत हो गया। बृहस्पति के नाखुश होने पर देवताओं ने उसे अपना पुरोहित बना लिया था। विश्वरूप की माता राक्षस कुल की थी।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

कदाचित् कोई शङ्कावादी महाशय- सा तेन संगता रात्रौ-(शि0 पु0 शतरुद्र 26 ।30) इत्यादि श्लोक का मनमान अर्थ घड़ कर पर्यङ्क विमिणा संगता आदि शब्दों का अभिप्राय निकालें कि-वह वैश्या शिव के साथ एक पलंग पर संगत पशुधर्म में प्रवृत्त हुई -तब तो हम उसे पञ्चम अन्यथासिद्ध ही सनकेंगे। क्योंकि व्याकरण कोश एवं अलङ्कार आदि किसी भी अर्थ विधायक शास्त्र की पद्धति से उपर्युक्त शब्दोंका ऐसा अभिप्राय नहीं बन सकता। स्व. श्री पं. कालूराम जी शास्त्री ने अपने पुराण वर्म में पर्यङ्क इस पद को जातिवाचक सिद्ध किया है, तदनुसार जातित्वादेकवचनम् इस नियम से पर्यङ्क यह एक वचन होता हुआ भी एकाधिक पलंगों का व्यावर्तक नहीं हो सकता, अर्थात्- महानन्दा और वैश्यनाथ एक ही पलंग पर लेटे थे यह बात उक्त वचन से सिद्ध नहीं की जा सकती।

इस श्लोक में वेदव्यास जी ने अपनी शब्दविन्यास चातुरी से श्री वैश्यनाथ जी को सब प्रकार के आक्षेपों से अछूता रखने के लिये उन्हें विधर्मी नाम से स्मरण किया है। अर्थात- व्यास जी को यदि श्री वैश्यनाथ भगवान् को साक्षात् विट्-धूर्त-किंवा वेश्यागाभी कहना अभीष्ट होता तो वे सीधे शब्दों में उन्हें केवल विट् नाम से याद करते, परन्तु मूल पाठ में विट् न कहकर विधर्मी कहने का यही अभिप्राय हो सकता है कि वे शिव भगवान् को विट् नहीं बल्कि विट् का स्वांगमात्र भर कर इस प्रकार की लीला का अभिनेता मात्र मानते हैं।

इसी प्रकार संगता शब्दों का अर्थ भी मैथुन, याभ या पशुधर्म में प्रवृत्त होना नहीं हो सकता क्योंकि किसी कोशकार या किसी भी ग्रन्थकार ने सम् उपसर्ग पूर्वक गम्लु धातु का अर्थ मैथुन करना नहीं लिखा, बल्कि भली प्रकार मिलना, तमीज से पेश आना ही इसका अभिप्राय हो सकता है। **क्रमशः...**

सरोजिनी नायडू जयंती

दयानिधि

भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो एक प्रतिष्ठित कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थीं। यह दिन समाज में महिलाओं के अपार योगदान को मान्यता देता है और लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है।

नायडू ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान और देश के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में चुना गया।

राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू को समर्पित है, जिन्हें भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है, जिनका जन्म 13 फरवरी, 1879 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख रहीं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं। बाद में, वह स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनीं।

राष्ट्रीय महिला दिवस न केवल सरोजिनी नायडू के योगदान का जश्न मनाता है बल्कि महिला सशक्तिकरण के महत्व को भी सामने लाता है। यह शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसरों की आवश्यकता की याद दिलाता है। भारत भर में महिलाओं ने बाधाओं को तोड़कर कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, जिससे यह साबित होता है कि प्रतिभा और दृढ़ता लैंगिक पूर्वाग्रहों से अधिक मजबूत हैं। सरोजिनी नायडू भारत में महिला अधिकारों की वकालत करने वाली अग्रणी थीं। उनके कुछ प्रमुख योगदानों में महिलाओं के मताधिकार और समान अधिकारों की प्रबल समर्थक थी।

उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना की गई।

अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करना, जिसमें द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग जैसे उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह शामिल हैं।

महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू की काव्यात्मक उत्कृष्टता के सम्मान में उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इतिहास रच दिया। अपनी कविता के माध्यम से नायडू ने भारत की संस्कृति, स्वतंत्रता के संघर्ष और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को खूबसूरती से दर्शाया।

संतुलन साधने का प्रयास है अमेरिकी समझौता

प्रभु चावला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडात्मक बाधाओं को समाप्त करने तथा पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि के नए युग का वादा किया है। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली और सोच-समझकर रचा गया। दो राष्ट्रवादी नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्टों के जरिये एक द्विपक्षीय समझौता गढ़ा, जिसके माध्यम से सैकड़ों अरब डॉलर के व्यापार को खोलने का दावा किया गया है। पर इसके साहसिक घोषणापत्र संस्थागत अस्पष्टता में ढंके रहे- जहां शुल्क कटौती की घोषणा तो हुई, पर उसे कानून का रूप नहीं दिया गया। जिन बाजारों के खुलने का दावा किया गया, वे ठोस बातचीत से निकले तथ्य नहीं, बल्कि मंचित अनुमानों जैसे लगे, क्योंकि सच्चाई तो नौकरशाही की उस धीमी और कठिन प्रक्रिया में निहित है, जिसे अभी सामने आना बाकी है।

समझौते पर देर से जारी संयुक्त बयान ने भी उत्तर से अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। अमेरिकी पक्ष का कथानक अत्यंत दुस्साहसी था। ट्रम्प ने घोषणा की कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को लेकर विवादों के बीच करीब 50 फीसदी तक बढ़ाए गए दंडात्मक शुल्क को घटाकर 18 फीसदी पर ला दिया जाएगा।

ट्रम्प के अनुसार, इसके बदले भारत ने अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर सभी शुल्क समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश देगा और रूसी तेल न लेकर अमेरिका तथा वेनेजुएला से तेल लेगा। साथ ही, भारत आने वाले वर्षों में 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा।

यह अमेरिकी विमर्श घरेलू उपभोग के लिए गढ़ा गया है, जिसका उद्देश्य 2025 तक करीब 53।5

अरब डॉलर तक पहुंच चुके उस वस्तु व्यापार घाटे को पाटने का भरोसा देना था, जहां भारत को अमेरिकी निर्यात करीब 42 अरब डॉलर ही रहा, जबकि भारत का अमेरिकी निर्यात 95 अरब डॉलर के पार चला गया। पर भारतीय प्रतिक्रिया ने इस अतिशयोक्ति को ठंडा कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते का स्वागत नए अवसरों के मार्ग के रूप में तो किया, पर ट्रम्प के तेल प्रतिबंध, कृषि पहुंच या पूर्ण शुल्क समाप्ति जैसे दावों का समर्थन करने से परहेज किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने केवल पारस्परिक 18 फीसदी टैरिफ सीमा पर अस्थायी समझ की बात मानी और अगले दशक में अमेरिकी ऊर्जा व उन्नत तकनीकों का आयात बढ़ाने की इच्छा जताई।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्र और नाजुक उद्योग पूरी तरह संरक्षित रहेंगे। संस्थागत वास्तविकता ने भी घोषणा और क्रियान्वयन के बीच की खाई उजागर की। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि इस समझ को औपचारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज में बदलने के लिए अभी ठोस दस्तावेज मौजूद नहीं है।

उन्होंने भारतीय व्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक अड़चनों की ओर इशारा किया, जो अचानक शुल्क परिवर्तन को असंभव बनाती हैं। अमेरिकी कार्यपालिका के विपरीत, जिसके पास शुल्क तय करने का व्यापक अधिकार है, भारत में आयात शुल्क में स्थायी कटौती के लिए जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन को सूचना देना और 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' सिद्धांत का पालन शामिल है।

जिसे ऐतिहासिक समझौता बताया गया, वह वास्तव में एक प्रारंभिक ढांचा है- यह द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था की पूर्ण और अंतिम संरचना नहीं, बल्कि टैरिफ टकराव को कम करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में अमेरिकी दावों और भारतीय वास्तविकता के बीच सबसे गहरी खाई दिखती है।

ट्रम्प के इस दावे को, कि मोदी ने रूसी तेल आयात समाप्त करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अमेरिकी व वेनेजुएला स्रोतों की ओर मोड़ने पर सहमति दी है, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भी दोहराया है। पर भारतीय अधिकारियों ने दृढ़ता से कहा कि ऊर्जा खरीद के फैसले मूल्य, आपूर्ति की विश्वसनीयता और रणनीतिक विविधीकरण के गणित से तय होंगे, कूटनीतिक दबाव से नहीं।

रूसी राजनयिकों ने भी पुष्टि की है कि उन्हें नई दिल्ली से कच्चे तेल की खरीद बंद करने संबंधी कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। कृषि क्षेत्र भी उपलब्धि से अधिक आकांक्षा के स्तर पर ही दिखाई देता है। अमेरिकी अनुमानों में भारत की कृषि सुरक्षा दीवारों में सेंध की कल्पना की गई- जिससे 1।4 अरब उपभोक्ताओं वाले बाजार तक अमेरिकी किसानों की पहुंच और बादाम से डेयरी तक अरबों डॉलर के नए निर्यात का वादा किया गया। यह कल्पनात्मक ढांचा ग्रामीण भारत की राजनीतिक-आर्थिक वास्तविकता की अनदेखी करता है।

ट्रम्प द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत द्वारा एकतरफा शुल्क समाप्त करने की घोषणा भारतीय आधिकारिक वक्तव्यों में कहीं प्रतिध्वनित नहीं हुई। यह राजनीतिक मंचन अलग-अलग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उजागर करता है। मोदी के लिए यह समझौता शक्ति का प्रतीक है- उन्हें ऐसे नेता के रूप में दिखाया गया,

जिसने एक अमेरिकी राष्ट्रपति को दंडात्मक शुल्क वापस लेने पर मजबूर किया। पर राहुल गांधी जैसे आक्रामक विपक्षी नेता इसे जीत के वेश में रणनीतिक आत्मसमर्पण बताते हैं। उन्होंने समझौते के पूरे दस्तावेज की संसदीय जांच की मांग की और चेतावनी दी है कि आकर्षक छवि के लिए कृषि और ऊर्जा सुरक्षा को गिरवी रखना आत्मनिर्भर भारत की भावना को कमजोर कर सकता है।

इन राजनीतिक विरोधाभासों के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों ने सावधानीपूर्ण आशावाद के साथ प्रतिक्रिया दी। अंतत: यह समझौता ट्रम्प शैली की अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी का प्रमाण है- शुल्क को दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल करना, भव्य मीडिया आयोजनों के जरिये सफलता की घोषणा करना और जटिल कानूनी रूपरेखा को बाद की नौकरशाही बैठकों पर छोड़ देना।

इससे भारत-अमेरिका व्यापार में वास्तविक पुनर्गठन होगा या केवल अस्थायी शांति, यह उन वार्ताओं पर निर्भर करेगा, जो अभी होनी हैं। जिस समझौते को इतनी धूमधाम से प्रचारित किया गया, यह न तो वह चमत्कार है, जिसका दावा ट्रम्प ने किया, और न ही वह तबाही, जिसका डर भारतीय विपक्ष जताता है।

आज का इतिहास

1786 अब्राहम बाल्डविन जॉर्जिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गए।
1795 अमेरिका में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुला।
1799 मैसाचुसेट्स विधायिका द्वारा पहला अमेरिकी बीमा कानून पारित किया गया।
1812 पहले चिलीयन अखबार अरोड़ा डी चिली राजनीतिक दर्शन से निपटने और नई राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में खड़े हुए।
1815 कैम्ब्रिज यूनियन सोसाइटी, दुनिया की सबसे पुरानी डिबेटिंग सोसाइटी में से एक है, जिसकी स्थापना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हुई थी।
1867 शहर के केंद्र में शहरी नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए ब्रुसेल्स में मुख्य जलमार्ग को दफनाने के लिए सेने को कवर करने पर काम शुरू हुआ।
1880 अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने एडिसन प्रभाव का अवलोकन किया, जिसने बाद में अंग्रेजी विद्युत इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा डिजाइन किए गए वैक्यूम ट्यूब डायोड के आधार का गठन किया।
1883 जर्मन संगीतकार रिचर्ड वैगनर वेनिस की इटली में दिल का दौरा पड़ने की मृत्यु हुई।
1891 ईरान में तंबाकू विरोधी अभियान की शुरुआत की गयी।
1917 माता हरि को पेरिस में जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया।
1945 सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया जिसमें एक लाख 59 हजार लोग मारे गये।
1960 अफ्रीकी अमेरिकी कॉलेज के छात्रों ने नैशविले, टेनेसी में तीन लंच काउंटरों पर नशविले सिट-इन का पहला मंचन किया, नस्लीय अलगाव को समाप्त करने के लिए एक अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान का हिस्सा।
1961 अमेरिकी जियोडेक्टर्स ने पता लगाया कि उन्होंने जो दावा किया था वह 500,000 साल पुरानी चट्टान थी जिसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ था।
1974 असंतुष्ट नोबेल विजेता अलेक्जेंडर सोलजेनिट्सिन को सोवियत संघ से निकाला गया।

अमेरिका से समझौते में हमारे कृषि हित

अभिजीत मुखोपाध्याय

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अंतरिम रूपरेखा में कृषि क्षेत्र नयी दिल्ली और भारतीय किसानों के लिए सबसे स्पष्ट रणनीतिक उपलब्धियों में से एक के रूप में चुपचाप उभरा है। वैश्विक खाद्य बाजारों में अनिश्चय के दौर में यह समझौता भारतीय कृषि उत्पादकों के लिए निर्यात अवसरों के विस्तार को देश के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की मजबूत सुरक्षा के साथ जोड़ता है। वाशिंगटन द्वारा जारी संयुक्त बयान में इस ढांचे को 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताया गया है, जो पारस्परिक और संतुलित आधार पर बाजार तक पहुंच का विस्तार करेगा। भारत के लिए इस पुनर्संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब भारतीय उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला के लिए अपने बाजार खोल रही है और भारत को दीर्घकालिक आर्थिक तथा भू-आर्थिक साझेदार के रूप में मान्यता दे रही है।

भारतीय अधिकारियों ने इस समझौते को घरेलू रियायतों के बजाय निर्यातकों के लिए नये अवसरों के रूप में प्रस्तुत किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रेखांकित किया है कि यह ढांचा 'भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खोलेगा और बड़ी संख्या में नये रोजगार पैदा करेगा'। यह संदेश ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में विशेष रूप से प्रभावी है, जहां कृषि निर्यात और उससे जुड़ी गतिविधियां स्थानीय अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं। भारत में किसी भी व्यापार समझौते की सबसे बड़ी राजनीतिक और नीतिगत कसौटी यह होती है कि वह छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका की रक्षा करता है या नहीं। इस दृष्टि से अंतरिम ढांचा पूरी तरह स्पष्ट है। गेहूं, चावल, पोल्ट्री, दूध और अन्य डेयरी व अनाज उत्पादों को टैरिफ रियायतों से 'पूरी तरह बाहर' रखा गया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन और पोल्ट्री जैसे वे कृषि व डेयरी उत्पाद, जिनका उत्पादन भारत में पर्याप्त मात्रा में होता है, शुल्क कटौती के दायरे में नहीं आएंगे।

मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों से पुष्टि होती है कि इस ढांचे के तहत भारत ने अमेरिका से सोयाबीन, मक्का, ईंधन एथेनॉल, कपास, डेयरी व पोल्ट्री उत्पादों के आयात के लिए बाजार नहीं खोले हैं, यानी यह समझौता न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली या इन संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को कमजोर नहीं करता।

इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखकर सरकार ने खाद्य सुरक्षा और किसान आय की आधारशिला मानी जाने वाली फसलों के चारों ओर एक स्पष्ट 'लाल रेखा' खींच दी है और यह संकेत दिया है कि वैश्विक बाजारों से जुड़ाव ग्रामीण स्थिरता की कीमत पर नहीं होगा। यह समझौता जहां नवाचारी है, वहीं यह भारतीय कृषि को मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाने और उच्च-मूल्य वाले बाजारों से गहराई से जोड़ने को प्रोत्साहित करता है। यह ढांचा अमेरिकी पारस्परिक शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने का भी हिस्सा है, जिससे हाल के वर्षों में घटती प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल करने में मदद मिलेगी।

भारतीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मसाले, चाय, कॉफी, काजू और विभिन्न प्रकार के फल जैसे कई कृषि उत्पादों पर अब अमेरिकी बाजार में शून्य या बहुत कम शुल्क लगेगा। भारत उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां उसे तुलनात्मक लाभ है- श्रम-प्रधान, जलवायु-विशेष और गुणवत्ता-आधारित फसलें, जो विदेशों में बेहतर कीमत प्राप्त कर सकती हैं। यह खासकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां निर्यात मांग सीधे स्थानीय कीमतों को प्रभावित करती है। अमेरिकी उपभोक्ताओं तक बेहतर पहुंच उन्हें विशेष कॉफी, प्रीमियम चाय, मसाले, काजू और उष्णकटिबंधीय फलों के लिए बड़ा और स्थिर बाजार प्रदान करती है, जिससे खेत-स्तर पर बेहतर कीमतें और गुणवत्ता सुधार में निवेश को बढ़ावा मिलता है।

संयुक्त बयान का एक कम दिखाई देने वाला, पर महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों से जुड़ी 'पुरानी गैर-शुल्क बाधाओं' को दूर करने और मानकों व अनुरूपता प्रक्रियाओं पर चर्चा करने की प्रतिबद्धता जतायी है। इसे अक्सर रियायत के रूप में देखा जाता है, पर यह भारतीय कृषि के लिए एक रणनीतिक अवसर भी है। मानकों पर संवाद के माध्यम से भारत अपने किसानों और निर्यातकों को दुनिया के सबसे कठिन बाजारों में से एक की तकनीकी, स्वच्छता और पादप-सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है। बेहतर ट्रेसबिलिटी (पता लगाने की क्षमता), गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन पर जोर लंबे समय में भारत की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात क्षमता को मजबूत करेगा।

व्यावहारिक रूप से मानकों के समन्वय और स्पष्ट नियमों से भारतीय खेपों की अस्वीकृति दर घटेगी, अनुपालन लागत कम होगी और उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैकहाउस, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। खासकर संगठित मूल्य श्रृंखलाओं और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से जुड़े किसानों के लिए इसका अर्थ है अधिक स्थिर मांग, बेहतर कीमतें और निर्यात मूल्य में अधिक हिस्सेदारी। यह अंतरिम ढांचा केवल शुल्क और कोटे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत भी देता है। 'भारतीय किसानों और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा' के साथ व्यापक बाजार पहुंच की नीति अपनाकर सरकार यह संदेश दे रही है कि भारत वैश्विक व्यापार में आगे बढ़ते हुए भी अपने ग्रामीण आधार की रक्षा करेगा।

अमेरिकी पक्ष के अनुसार, भारत कुछ चुनिंदा अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों-जैसे पशु आहार के लिए सूखे अनाज, लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट-पर शुल्क घटाएगा। ये उत्पाद भारत के लिए पूरक या गैर-प्रतिस्पर्धी हैं और घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचाये बिना विशिष्ट जरूरतों या सीमित उपभोक्ता वर्ग की मांग पूरी करते हैं। समग्र रूप से यह एक संतुलित और विश्वास-निर्माण वाला दृष्टिकोण दर्शाता है।

यह अंतरिम व्यापार ढांचा केवल एक कूटनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि पर विश्वास का वक्तव्य है। जहां आवश्यक हो, वहां संरक्षण और जहां संभव हो, वहां महत्वाकांक्षा को जोड़ते हुए सरकार ने ऐसा समझौता तैयार किया है, जो आने वाले वर्षों में किसानों के लिए वास्तविक अवसर और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है-और वैश्विक एकीकरण को खतरे के बजाय विकास के मंच में बदल सकता है।

चुनाव से पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले

देवेश त्रिपाठी

बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए मतदान से सिर्फ तीन दिन पहले एक हिंदू व्यापारी की नृशंस हत्या, जो देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की ताजा कड़ी है, वाकई क्षुब्ध करने वाली है। हैरानी की बात है कि यह वारदात भी उसी मैमनसिंह जिले में हुई है, जहां कुछ महीने पहले बजेंद्र बिस्वास नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी और फिर इसी क्षेत्र में एक फैक्टरी कर्मचारी दीपू चंद्र दास को भी भीड़ ने पहले पीटा और फिर जलाकर मार डाला था। ताजा मामले में भी हमलावरों ने 62 वर्षीय व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की निर्मम हत्या कर शव को उनकी दुकान के भीतर ही फेंक दिया। अगस्त, 2024 में जब शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार की बागडोर मोहम्मद यूनुस ने संभाली थी, तब उम्मीद जताई गई थी कि वह लोकतंत्र की बहाली और सामाजिक सद्भाव बहाल करने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनुस शासन के दौरान अल्पसंख्यकों पर 2,900 से अधिक हमले हो चुके हैं। ऐसी 51 घटनाएं तो पिछले वर्ष दिसंबर में ही हुई थीं। ये आंकड़े गवाह हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को किस कदर छूट मिली हुई है। अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के बजाय यूनुस सरकार ने इन्हें झूठ बताकर खारिज करने की कोशिश की है। नतीजा सामने है। शेख हसीना के शासन में जिन कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगी थी, वे अब खुलेआम सक्रिय हैं। इस पूरे परिदृश्य में यूनुस की

भूमिका खलने वाली है, जो पिछले डेढ़ वर्ष से पाकिस्तान को खुश करने में ही लगे रहे, लेकिन इससे भी दुखद यह है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की लगातार हत्याओं के बावजूद अब तक बांग्लादेश पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिशें होती नहीं दिखी हैं। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का आईना भी होते हैं। इस आईने में अगर भय व हिंसा की छवि उभरती है, तो यह किसी भी देश के लिए चिंताजनक है। बांग्लादेश के सामने अब भी अवसर है कि वह सख्त और निष्पक्ष कदम उठाकर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे, क्योंकि ऐसा करना केवल उसका कानूनी और नैतिक दायित्व ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की बुनियादी शर्त भी है। अगर ऐसा हुआ, तभी आम चुनाव बांग्लादेश के लोकतंत्र को और परिपक्व बना सकता है, वरना वह जिस दिशा में बढ़ रहा है, आशंका है कि कहीं उसका भी हाल पाकिस्तान जैसा न हो।

बांग्लादेश चुनाव बाद तय होगी दोस्ती या दुश्मनी

डॉ हिदायत अहमद खान

बांग्लादेश में अचानक जेन-ज़ी आंदोलन और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटते हुए भारत में शरण लेती हैं। इसके बाद प्रमुख सलाहकार यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता की बागडोर संभालती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तोड़ने-मरोड़ने का खेल शुरु हो जाता है। सबसे भरोसेमंद और हितैषी पड़ोसी मित्र देश को दूर करने और दुश्मनों को गले लगाने का काम भी होता है। इस दौरान न हिंसा रुकती है और न ही हालात बदलते हैं। इसी के साथ चुनाव की तारीख भी सामने आ जाती है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर भर नहीं हैं, बल्कि वे देश की वैचारिक दिशा, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और पड़ोसी देशों खासकर भारत से रिश्तों की जमीन तय करने वाले निर्णायक मोड़ साबित होंगे। कुल 300 सीटों में से 299 सीटों पर मतदान और 'जुलाई चार्टर' पर जनमत संग्रह के साथ यह चुनाव कई स्तरों पर महत्वपूर्ण होने वाले है। बावजूद इसके जिस राजनीतिक माहौल में चुनाव कराए जा रहे हैं, उससे इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर पहले से ही गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति न दिए जाने को लेकर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली यह पार्टी बांग्लादेश की राजनीति की केंद्रीय धुरी रही है। ऐसे में उसका चुनावी मैदान से बाहर होना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की आत्मा को कमजोर करता है। अवामी लीग के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने चुनाव को सुनियोजित बताते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से गढ़ा गया है कि एक विशेष विचारधारा को सत्ता में बनाए रखा जा सके। उन्होंने ऐसे चुनाव का बहिष्कार करने की अपील अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक से कर डाली। यहां कहना गलत भी नहीं होगा कि यदि विपक्ष का एक बड़ा दल ही चुनावी

प्रक्रिया से बाहर हो, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वत: संदिग्ध हो जाती है। बहरहाल चुनाव हो रहे हैं ऐसे में जीत-हार के दावे भी सामने आ गए हैं। चुनावी मुकाबला मुख्यत: तारिक रहमान के नेतृत्व वाले बीएनपी गठबंधन और जमात-ए-इस्लामी व नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के 11 दलों के गठबंधन के बीच माना जा रहा है। अनुमानित वोट प्रतिशत बताता है, कि मुकाबला कांटे का है। 13 वर्षों के प्रतिबंध के बाद जमात-ए-इस्लामी का चुनावी मैदान में लौटना भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 2008 के बाद पहली बार वह चुनाव लड़ रही है। खुद को मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित करने के प्रयास में जमात ने इस बार एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया है, हालांकि किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर जमात सुर्खियां भी बटोर रही है। इस मामले में पार्टी का तर्क है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह तर्क समावेशी राजनीति की कसौटी पर अधूरा लगता है।

बांग्लादेश के आम चुनाव का एक बड़ा आयाम विदेश नीति भी है। जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे सम्मान और मर्यादा के आधार पर विदेश संबंधों को पुनर्परिभाषित करना चाहते हैं। पिछले 16 वर्षों की विदेश नीति को एक देश अर्थात भारत केंद्रित बताकर उसकी आलोचना की जा रही है। तीस्ता जल बंटवारा, सीमा पर होने वाली घटनाएं और साझा नदियों के पानी का मुद्दा प्रमुख चुनावी विषय बन चुके हैं। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत के साथ संबंध अब निर्विवाद नहीं रहे। यदि नई सरकार भारत के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाती है, तो द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। सुरक्षा कारण बताकर भारत द्वारा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक न भेजना भी इन्हीं संकेतों की ओर इशारा करता है। यह या तो सतर्क दूरी का संकेत है या फिर आंतरिक परिस्थितियों को लेकर एक प्रकार की प्रतीक्षा की नीति। वैसे यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार भी है। सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इन सभी पर ढाका की राजनीतिक दिशा का सीधा असर पड़ता है। चिंता का विषय यह भी है कि चुनावी विमर्श में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता दिख रहा है। यदि कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं, तो अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। बांग्लादेश ने पिछले दशक में आर्थिक प्रगति और सामाजिक सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है।

राजनीतिक अस्थिरता या वैचारिक टकराव इस उपलब्धि को कमजोर कर सकता है। ऐसे में यह चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और क्षेत्रीय संतुलन की परीक्षा है। नई सरकार यह तय करेगी कि देश सहयोग और संवाद की राह पर चलेगा या टकराव और अविश्वास की ओर मुड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध इतिहास, भूगोल और साझा संघर्षों से जुड़े हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ढाका में जो भी सत्ता में आए, वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्राथमिकता देगा। क्योंकि अंतत: स्थिर, समावेशी और संतुलित बांग्लादेश ही पूरे दक्षिण एशिया के हित में है।

डिजिटल क्रांति पर साइबर प्रहार गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

डिजिटल युग ने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं ने लेन-देन को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया है। आज एक सामान्य नागरिक भी कुछ सेकंड में देश के किसी भी कोने में धन भेज सकता है, बिल जमा कर सकता है या निवेश कर सकता है। यही डिजिटल क्रांति 'नए भारत' और 'विकसित भारत' की आधारशिला मानी जा रही है। किंतु इसी क्रांति के साथ एक गहरी विडंबना भी उभरकर सामने आई है-डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर लूट की भयावह बढ़ोतरी। हजारों करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की घटनाएँ न केवल आमजन को आर्थिक रूप से आहत कर रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा रही हैं।

डिजिटल व्यवस्था की मूल आत्मा 'विश्वास' है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल स्क्रीन पर उभरे एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है या किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो वह केवल तकनीक पर ही नहीं, बल्कि उस संपूर्ण तंत्र पर भरोसा करता है जो उसे सुरक्षित लेन-देन का आश्वासन देता है। किंतु जब यही विश्वास ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, निवेश घोटालों और पहचान चोरी के कारण टूटने लगता है, तब डिजिटल विकास की पूरी अवधारणा कमजोर पड़ने लगती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में नकली नोटों की भरमार हो जाए तो मुद्रा पर विश्वास डगमगा जाता है, उसी प्रकार यदि डिजिटल लेन-देन में ठगी सामान्य अनुभव बन जाए, तो नागरिक डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाने लगते हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत हानि का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के लिए भी खतरे की घंटी है। परंपरागत अपराधों और डिजिटल अपराधों की तुलना करें तो दोनों के स्वरूप और प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। पहले चोरी या डकैती किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती थी, अपराधी की पहचान अपेक्षाकृत स्पष्ट होती थी और जांच प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी। डिजिटल अपराधों में अपराधी अदृश्य है, वह किसी दूसरे राज्य या देश में बैठकर वारदात कर सकता है, और कुछ मिनटों में सैकड़ों लोगों को निशाना बना सकता है। पारंपरिक अपराध में जोखिम अपराधी के लिए अधिक था, डिजिटल अपराध में जोखिम कम और लाभ अधिक है। यही असंतुलन

इसे अत्यंत खतरनाक बनाता है।

एक अन्य तुलनात्मक पक्ष यह है कि डिजिटल अपराधों में पीड़ित की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी अलग होती है। ठगी का शिकार व्यक्ति स्वयं को अपराधी के सामने असहाय पाता है। पुलिस और साइबर क्राइम कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी जब उसे तकनीकी कारणों का हवाला देकर लौटा दिया जाता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास जन्म लेता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जटिल है, समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, और समय पर कार्रवाई न होने से धन की रिकवरी असंभव हो जाती है। इससे यह धारणा बनती है कि डिजिटल अपराध का कोई वास्तविक दंड नहीं है। सरकार और न्यायपालिका ने समय-समय पर इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है। शीर्ष अदालत द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखना इस बात का संकेत है कि यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक आक्रमण भी हो सकता है। किंतु नीति-निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की दूरी अभी भी बनी हुई है। अनेक प्लेटफार्म और हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी स्पष्ट दिखती है। यदि शिकायत के बाद प्रारंभिक गोल्डन ऑवर में ही बैंक खाते फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन ट्रैक करने की प्रभावी व्यवस्था न हो, तो बाद की प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह जाती है।

वित्तीय प्रणाली की दृष्टि से देखें तो डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना निवेश, उपभोग और बैंकिंग व्यवहार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आमजन को यह आशंका सताने लगे कि ऑनलाइन निवेश योजनाएँ या भुगतान सुरक्षित नहीं हैं, तो वह नकद लेन-देन की ओर लौट सकता है। यह प्रवृत्ति सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था की नीति को कमजोर करेगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशकों के लिए भी यह संकेत नकारात्मक हो सकता है कि साइबर सुरक्षा का ढांचा पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है। अत: यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का भी केंद्रीय प्रश्न है। समाधान के स्तर पर तुलनात्मक रूप से देखें तो विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रखा है। वहाँ विशेषीकृत एजेंसियाँ, उच्च प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञ, त्वरित डेटा साझा करने की प्रणाली और सख्त दंडात्मक प्रावधान हैं। भारत में भी साइबर क्राइम ब्यूरो और डिजिटल सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, परंतु उनकी क्षमता, संसाधन और प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस बल को केवल पारंपरिक अपराधों की नहीं, बल्कि डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण की भी विशेषज्ञता दी जानी चाहिए। जब तक जांच एजेंसियाँ तकनीकी रूप से अपराधियों से एक कदम आगे नहीं होंगी, तब तक रोकथाम कठिन रहेगी।

एक महत्वपूर्ण पक्ष नागरिक जागरूकता का भी है। तकनीक जितनी उन्नत होती है, अपराधी भी उतने ही नए तरीके अपनाते हैं। अत: केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि लोग संदिग्ध लिंक, कॉल और निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि जागरूकता का दायित्व पीड़ित पर डालकर व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सुरक्षा का मूल दायित्व तंत्र का है, नागरिक का नहीं। भ्रष्टाचार और लापरवाही भी इस समस्या को जटिल बनाते हैं। यदि बैंक या भुगतान प्लेटफार्म समय पर कार्रवाई नहीं करते, या आंतरिक मिलीभगत से फर्जी खाते संचालित होते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट प्रणाली, जवाबदेही और कठोर दंड अनिवार्य हैं। डिजिटल प्लेटफार्मों की केवाईसी प्रक्रिया को अधिक कठोर और वास्तविक बनाना होगा, ताकि फर्जी पहचान के माध्यम से खाते खोलना कठिन हो।

अंतत: डिजिटल क्रांति का उद्देश्य सुविधा, पारदर्शिता और समृद्धि है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसका नैतिक औचित्य कमजोर पड़ जाएगा। भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल परिवर्तन को रोकना संभव नहीं, और न ही यह वांछनीय है।

चीन भी यूएनएससी में भारत के दावे का किया समर्थन

नीरज कुमार दुबे

भारत और चीन के बीच रिश्तों की जमी बर्फ अब पिघलने लगी है और यह बदलाव केवल सीमा तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि व्यापार, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन तक फैलता नजर आ रहा है। नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओशु के बीच हुई सामरिक संवाद बैठक ने यह साफ कर दिया कि दोनों देश टकराव की लंबी थकान के बाद अब ठोस लाभ की राह तलाश रहे हैं। बातचीत का मुख्य आधार रहा व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखना। हम आपको याद दिला दें कि करीब 4 वर्ष तक चले पूर्वी लद्दाख गतिरोध ने दोनों देशों के संबंधों को झकझोर दिया था। उसके बाद हुए सीमा समझौते और शीर्ष नेतृत्व की बैठकों के फल अब सामने आने लगे हैं। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही व्यापक रिश्तों की बुनियाद है। इसी सोच के साथ द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी अड़चनों को राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से सुलझाने पर जोर दिया गया। बैठक में वायु सेवा समझौते को जल्द नया रूप देने, जन से जन संपर्क बढ़ाने और प्रवेश अनुमति पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भरोसे की बहाली का संकेत माना गया और इसके दायरे को आगे बढ़ाने की आशा जताई गई। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात रही चीन का यह कहना कि वह भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा को समझता और उसका सम्मान करता है। यह रुख पहले के ठंडे या विरोधी रवैये से अलग माना जा रहा है। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं और हर एक के पास वीटो शक्ति है। ऐसे में किसी नए स्थायी सदस्य के रास्ते में इन पांचों की सहमति निर्णायक होती है। पहले चार स्थायी सदस्यों ने अलग अलग समय पर भारत के दावे का समर्थन जताया है, जबकि चीन का रुख अस्पष्ट या ठंडा रहा। अब बीजिंग की यह नरमी नई चर्चा को जन्म दे रही है। चीन ने यह भी कहा कि बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति में दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी साझेदार के रूप में देखना चाहिए। दोनों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, ग्लोबल साउथ की एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात दोहराई। साथ ही भारत की इस वर्ष की ब्रिक्स अध्यक्षता और भारत में होने वाली ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए चीन ने समर्थन जताया। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते आगे बढ़ाए हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध बना रहा है। ऐसे में चीन का भारत की ओर व्यापार और कूटनीति का हाथ बढ़ाना केवल सद्भाव नहीं, बल्कि रणनीति भी माना जा रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं यदि टकराव कम कर सहयोग बढ़ाती हैं, तो एशिया ही नहीं, पूरे विश्व का शक्ति गणित बदल सकती हैं। पिछले छह महीनों में भारत चीन संबंधों में जो सुधार दिखा है, उसमें शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातें, सैन्य स्तर पर संवाद और आर्थिक संपर्क की बहाली शामिल है। हालांकि अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर संवाद की पटरी पर लौटना अपने आप में बड़ा बदलाव है। देखा जाये तो भारत चीन रिश्तों में यह नरमी केवल दोस्ती की कहानी नहीं, बल्कि कठोर यथार्थ की राजनीति है। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और सामरिक समीकरण ने बीजिंग को संकेत दिया है कि नई दिल्ली अब विकल्पों से भरपूर है। ऐसे में चीन का लहजा बदलना स्वाभाविक भी है और मजबूरी भी। वह नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह पश्चिमी खेमे की ओर झुक जाए और एशिया में उसके लिए संतुलन बिगड़ जाए। भारत के लिए भी यह मौका है, पर खतरे से खाली नहीं। चीन के शब्द मधुर हो सकते हैं, पर उसकी नीति हमेशा अपने हित के इर्द गिर्द घूमती है। सीमा पर शांति की बात स्वागत योग्य है, पर जमीन पर सख्त चौकसी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। इतिहास बताता है कि भरोसा और सतर्कता दोनों साथ साथ चलाने पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर चीन का नरम संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना सुधार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन केवल समझने और सम्मान करने से काम नहीं चलेगा, खुला और स्पष्ट समर्थन ही असली कसौटी होगा। बहरहाल, यदि भारत और चीन सच में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर सहयोग का रास्ता निकाल लेते हैं, तो इसके वैश्विक और क्षेत्रीय भूराजनीतिक निहितार्थ गहरे होंगे। एशिया में तनाव घट सकता है, आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थिर हो सकती हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो सकती है।

वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ इन जगहों पर घूमने जाएं, ट्रिप रहेगी यादगार

फरवरी का महीना लव बर्ड्स के लिए बेहद खास माना जाता है। फरवरी महीने को प्यार का महीना कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बनाते है। यदि आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन रोमांटिक जगहों पर जरुर जाएं। यह ट्रिप आपकी बेहद यादगार रहेगी।

फरवरी का महीना प्यार महीना कहा जाता है। इस महीने में वैलेंटाइन डे आता है, जो कि कपल इसे सेलिब्रट करते हैं। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन वीक शुरु हो जाएगा। इस खास महीने में लव बर्ड्स कहीं न कहीं घूमने का प्लान जरुर बनाते हैं। अगर आप भी फरवरी में अपने पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं और घूमने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आइए आपको बताते हैं कि आप किस रोमांटिक प्लेस पर घूमने जा सकते हैं।

दार्जिलिंग

फरवरी के महीने में घूमने के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि चाय के बागानों से घिरी हुई है। यहां पर टाइगर हिल में एक टॉय ट्रेन चलती है इसमें बैठकर आप सुंदर पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के लिए यह जगह काफी अच्छी है।

महाबलेश्वर

अगर आप भी पार्टनर के साथ फरवरी में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक अच्छी डेस्टिनेशन में से एक है। यह जगह हरे-भरे प्रकृति और सुकून भरे मौसम के साथ ही पहाड़ों के नजारे देख सकते हैं। झरने और झील देख सकते हैं। मुंबई के पास इस जगह पर लोग वीकेंड पर जाना काफी पसंद करते हैं।

गोवा

अगर आप फरवरी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ गोवा जा सकते हैं। यहां पर आप समुद्र के किनारे सनसेट का मजा ले सकते हैं। यहां पर घूमने कई जगहे हैं। गोवा में आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं और आप समुंद्र किनारे अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं।

हम्पी

खूबसूरत नजारे के लिए हम्पी काफी फेमस है। यूनेस्को की विश्व धरोहर मानी जाने वाली यह जगह एक हनीमून के लिए भी सबसे बढ़िया है। यहां पर केले के बागान और बिखरी पहाड़ियां हम्पी शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक हो सकती हैं। हम्पी में घूमने के लिए काफी जगहें है।

ट्रैकिंग के शौकिनों के लिए यह एक आदर्श स्थल है येलागिरी

येलागिरी की प्रमुख आकर्षणों में से एक येलागिरी झील है, जहां पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इस झील के चारों ओर हरे-भरे बाग-बगिचे और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जो पर्यटकों को विश्राम और शांति का अहसास कराती है।

येलागिरी, तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा पर्वतीय स्थल है, जो चित्ताकर्षक प्राकृतिक दृश्यावलियों, शांतिपूर्ण वातावरण और रोमांचक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान विशेष रूप से उन पर्यटकों के लिए आदर्श है जो शहरी हलचल से दूर शांतिपूर्ण जगहों की तलाश में रहते हैं। यहां के हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत झीलें और सुरम्य ट्रैकिंग रूट्स पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं येलागिरी के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में।

1. येलागिरी झील

येलागिरी की प्रमुख आकर्षणों में से एक येलागिरी झील है, जहां पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इस झील के चारों ओर हरे-भरे बाग-बगिचे और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जो पर्यटकों को विश्राम और शांति का अहसास कराती है। यहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी हैं, जो इसे परिवारों के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है।

2. स्वामीमलई हिल्स

स्वामीमलई हिल्स येलागिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। ट्रैकिंग के शौकिनों के लिए यह एक आदर्श स्थल है, क्योंकि यहां की चढ़ाई आपको अद्वितीय दृश्य और प्रकृति के नज़ारे प्रदान करती है। इसके ऊपर से आसपास के इलाके का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है।

3. पंगलिंगम झरना

येलागिरी के पंगलिंगम झरने में गिरते हुए पानी की आवाज़ और ठंडी हवा पर्यटकों को ताजगी का एहसास कराती है। यह झरना प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकिनों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहां पहुंचने के लिए कुछ ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, जो इस स्थान को और भी रोमांचक बनाती है।

4. जैन मंदिर

येलागिरी में स्थित जैन मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है और यहां के दर्शन करने से एक अलग ही अनुभव मिलता है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है।

5. विलियानुर झरना

यह झरना येलागिरी के पास स्थित एक और लोकप्रिय स्थान है। यहां पर गिरते पानी के झरने के साथ-साथ आसपास की हरी-भरी वादियों का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इस झरने के पास घूमने और प्रकृति के नजारे का आनंद लिया जा सकता है।

6. येलागिरी पार्क

यह पार्क येलागिरी झील के पास स्थित है और यहां आप परिवार के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए खेलकूद के सामान और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह स्थल विशेष रूप से परिवारों के लिए एक आदर्श गंतव्य है।

7. अक्टिविटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स

येलागिरी में कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग आदि। इन गतिविधियों के माध्यम से आप प्रकृति के करीब जाकर रोमांचक अनुभव ले सकते हैं।

8. जंगल सफारी

अगर आप जंगल और वन्यजीवों के प्रेमी हैं, तो येलागिरी के आस-पास के जंगलों में सफारी का अनुभव भी ले सकते हैं। यहां के घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

9. सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्य

येलागिरी के पहाड़ों से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। यहां के पहाड़ी इलाकों में सूरज के निकलने और ढलने के समय के दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह दृश्य आपके लिए यादगार होगा।

येलागिरी एक शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल है। यहाँ का वातावरण, झीलें, झरने, पहाड़ और ट्रैकिंग रूट्स आपको शांति और रोमांच का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करते हैं। यदि आप एक यात्रा प्रेमी हैं और प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना चाहते हैं, तो येलागिरी एक बेहतरीन गंतव्य हो सकता है।

इस सुरम्य पहाड़ी स्थल पर यात्रा करते हुए आप न केवल अपनी मानसिक शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं।

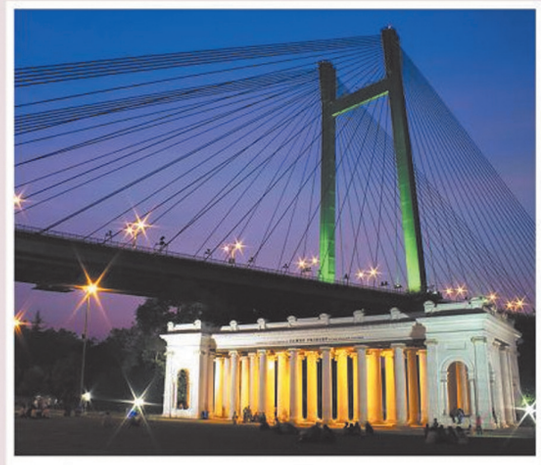

कोलकाता की इन 3 जगहों पर सेलिब्रेट करें बर्थडे, खास और यादगार बन जाएगा दिन

किसी खास जगह पर जाकर बर्थडे मनाकर लोग इसको एक यादगार पल बनाना चाहते हैं। हम सभी बर्थडे के दिन को खास बनाने के लिए खास लोकेशन की तलाश करते हैं। अपने किसी खास के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना सबसे अनोखा एहसास होता है। कुछ लोग अपने परिवार या पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए किसी सुकून देने वाले जगह पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोलकाता की कुछ ऐसी फेमस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप बर्थडे पार्टी प्लान कर सकते हैं।

प्रिंसेप घाट

हुगली नदी के किनारे प्रिंसेप घाट का दृश्य और शांति से भरा माहौल आपके जन्मदिन को यादगार बना देगा। प्रिंसेप घाट की सुंदरता और ताजगी बर्थडे पार्टी के लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप अपने बर्थडे को अधिक यादगार बनाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर सनसेट का दृश्य देखते हुए बर्थडे पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। यह जगह सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ज्यादा सुंदर और बेहतरीन हो जाती है। कोलकाता की यह फेमस जगह घूमने के लिए काफी अच्छी है।

पार्क स्ट्रीट

अगर आप भी कोलकाता में बर्थडे पर घूमने के लिए पार्ट स्ट्रीट जाने का प्लान कर सकते हैं। यह कोलकाता के सबसे स्टाइलिश पर्यटक आकर्षणों में से एक है। जोकि फूड स्ट्रीट और नाइट लाइफ हब के लिए फेमस है। अक्सर लोगों को बर्थडे पार्टी राय या शाम के समय प्लान करना पसंद होता है।

इलियट पार्क

बता दें कि इलियट पार्क बैठने और आराम करने के लिए काफी अच्छी जगह है। शहर के केंद्र में स्थित यह पार्क बेहद शांत और हरा-भरा है। यहां का शांतिपूर्ण वातावरण आपका दिल जीत लेगा। बर्थडे पार्टी के लिए आप इस जगह का चयन कर सकते हैं। आप यहां पर घंटों समय बिता सकते हैं। यह पार्क दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। ऐसे में आप इस बीच यहां आ सकते हैं। यह कोलकाता का सबसे सुंदर पार्क है। वहीं यह पार्क बच्चों के साथ घूमने के लिए बेहद अच्छी जगह है।

स्वर्ग से भी सुंदर इस जगह पर मिलेगा मानसिक सुकून, रहने-खाने में नहीं खर्च होंगे हजारों रुपए

आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाना बजट के अंदर होने के साथ ही आप प्रकृति के बीच समय भी बिता सकेंगे। यहां पर गंगा का कल-कल बहता ठंडा पानी, गंगा आरती, मंदिर, सुंदर घाट आपको मानसिक सुकून देगा।

घर और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालने के कारण लोग मशीन की तरह काम करते हैं। ऐसे में इस व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण लोग अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कई बार लोग काम का इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि शरीर थक जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में आपको फौरन एक ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि यह ब्रेक आपको मानसिक शांति देने के साथ अंदर से हील करने का काम करता है।

इसलिए आपको काम से ब्रेक लेकर किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, जहां पर आप खुलकर सांस ले सकें और शांति व सुकून का अनुभव कर सकें। अगर आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाना बजट के अंदर हो और आप प्रकृति के बीच समय भी बिता सकेंगे। दरअसल हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर पूरे विश्व भर से लोग योग सिखने के लिए आते हैं। यह जगह और कोई नहीं बल्कि ऋषिकेश है। यहां पर गंगा का कल-कल बहता ठंडा पानी, गंगा आरती, मंदिर, सुंदर घाट और चारों ओर योग व आध्यात्म का नजारा आपको मानसिक सुकून देने का काम करेगा।

इस तरह करें ऋषिकेश जाने की प्लानिंग

दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए आपको कई बस और ट्रेन मिल जाएंगी। बसों का किराया 300-400 रुपए के बीच होता है। इसके साथ ही ट्रेन के टिकट की कीमत भी करीब-करीब इतना ही होगा।

लोकल ट्रांसपोर्ट

दिल्ली से ऋषिकेश जाकर प्राइवेट कार या फिर कैब के इस्तेमाल की जगह लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्राइवेट कैब जहां आपको 200-300 रुपए खर्च करने होंगे। तो वहीं लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर आपका खर्चा 40-50 रुपए ही आएगा। बता दें कि आपको ऋषिकेश बस स्टॉप से कई लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे।

आश्रम में रहें

आप ऋषिकेश में होटल की जगह हॉस्टल में स्टे करें। हॉस्टल की शुरूआत 500 रुपए से होती है। अगर आप राम झूला के पास हैं, तो आपको यहां पर कई आश्रम मिल जाएंगे।

स्ट्रीट फ़ूड का लें मजा

अगर आप चाहें तो राम झूला के पास या लक्ष्मण झूला के पास खाने-पीने के लिए आपको महंगे से लेकर बजट तक में कई पैकेज मिल जाएंगे। आप यहां पर स्ट्रीट फूड का भी मजा ले सकते हैं। आपको यहां पर 100 रुपए में खाने-पीने को काफी कुछ मिल जाएगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर को उनके चैंबर में गाली दी थी

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को फिर से दोहराया कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को उनके चैंबर में गाली दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा बहस और चर्चा में विश्वास करती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक या मौखिक धमकी का समर्थन नहीं करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने एक कांग्रेस सांसद द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक अवैध वीडियो साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैंबर में घुस गए, उन्हें गाली दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी। रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि यह एक कांग्रेस सांसद द्वारा बनाया गया अवैध वीडियो क्लिप है, जिसमें 20-25 कांग्रेस सांसद माननीय स्पीकर के चैंबर में घुस गए, उन्हें गाली दी और माननीय प्रधानमंत्री को धमकी दी। हमारी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और सांसदों को शारीरिक रूप से धमकी देने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करती है।

प्रधानमंत्री मोदी 14 को असम के दौरे पर रहेंगे

डिब्रूगढ़। असम में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचार और कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य दौरा करने वाले हैं। इसके लिए डिब्रूगढ़ जिले में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार कराई गई है। प्रधानमंत्री का विमान इसी जिले में उतरेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 11 फरवरी को दी। दौरे का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है और इसमें अपर असम और गुवाहाटी दोनों शामिल हैं। वहां से वह मोरन के लिए रवाना होंगे और सुबह 10 बजे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) पर उतरेंगे। मोरन दौरे के दौरान फाइटर जेट्स का एयर शो होगा, जिसमें कई विमान हाइवे एयरस्ट्रिप पर उतरेंगे।

डीएमके नेता ने सीट बंटवारे पर अटकलों को किया खारिज

चेन्नई। डीएमके के वरिष्ठ नेता टी.के.एस. एलंगोवन ने गुरुवार को डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के भीतर मतभेद की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला है। एलंगोवन ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच औपचारिक सीट-बंटवारे की बातचीत 22 फरवरी से शुरू होगी, जिससे सत्ता-साझाकरण की मांगों को लेकर बढ़ते मतभेद की अफवाहें खत्म हो जाएंगी। उनका यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए दबाव बना रही है, जिसमें कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग भी शामिल है, जो 2021 के विधानसभा चुनावों में लड़ी गई 25 सीटों की तुलना में काफी अधिक है। सूत्रों ने संकेत दिया था कि डीएमके मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखना पसंद करती है।

असम सीएम के मानहानि केस पर अंतरिम रोक

गुवाहाटी। असम के कामरूप जिले में एक अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मानहानि केस पर अहम निर्देश दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपये के मानहानि का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई पर सीएम की संपत्ति से जुड़ा कोई भी बयान देने से मना किया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। अदालत 9 मार्च को मामले में अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में गौरव गोगोई समेत सात लोगों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी संपत्ति और ईमानदारी के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे बयान दिए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ सीएम ने 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का केस दर्ज किया था।

श्रम सुधारों और आर्थिक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद

कोलकाता। चार नई श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को देशव्यापी बंद का एलान किया है। हालांकि यह बंद पश्चिम बंगाल में असर डालने में नाकाम रहा है और बंगाल में हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य तौर पर संचालित हो रहे हैं। 14 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त तौर पर बंद का आह्वान किया है। इन ट्रेड यूनियनों की मांग है कि चार नई श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए और कामगारों और किसानों को प्रभावित करने वाली नीतियों को भी वापस लिया जाए। कर्मचारी और अध्यापक संगठनों ने भी ट्रेड यूनियन के इस बंद का समर्थन किया है। वाम दलों का गढ़ रहा बंगाल इस बंद के असर से अछूता दिख रहा है। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां कामगार विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्रविरोधी होने के साथ-साथ कॉरपोरेट समर्थक हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर का दावा है कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, ओडिशा और बिहार में बंद का व्यापक असर है।

लोकसभा में राहुल और जगदंबिका पाल में तीखी नोकझोंक

बोले- मेरी सुनते तो विपक्ष में न होते

नईदिल्ली। केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही जगदंबिका पाल के बीच तीखी बहस हुई। गांधी ने पाल को पूर्व कांग्रेसी सदस्य कहकर संबोधित किया, जिस पर अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। पाल ने हिंदी में जवाब दिया कि मेरी सलाह ले लिए होते, तो आज भी विपक्ष में नहीं बैठे रहते। इसी को लेकर आज पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपने शब्दों और भाषा की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। क्या इस संसदीय लोकतंत्र में ऐसा करना उचित है?

उन्होंने आगे कहा कि निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि 2013 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें हमारे मक्का और किसानों के अनाज की स्थिति का जिक्र था, और यह भी तय हुआ था कि राशन की दुकानें बंद रहेंगी और किसी को भी मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस फैसले को पलट दिया। क्या कांग्रेस सरकार ने अपनी पहचान गिरवी रख दी, आत्मसमर्पण कर दिया या देश बेच दिया? या शर्म अल शेख में कांग्रेस-यूपीए सरकार द्वारा लिया गया फैसला।

पाल ने कहा कि वह सरकार की जितनी चाहे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप वह लगा रहे हैं, जिस तरीके से लगा रहे हैं, वह देश को गुमराह कर रहे है। दुनिया देश की उपलब्धियों के बारे में जानती हैं- कैसे भारत ने कोविड के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचाया है। बुधवार को सदन में तीखी बहस छिड़ गई जब गांधी जी ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि इससे भारत के मूल हितों से समझौता हुआ है।

उन्होंने इस समझौते को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करार दिया और दावा किया कि सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हितों और डिजिटल डेटा का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया है। मार्शल आर्ट का उदाहरण देते हुए गांधी ने कहा कि बातचीत का अंत गला घोंटने से नहीं होना चाहिए। उन्होंने सदन को बताया कि मार्शल आर्ट में पहले पकड़ बनती है, फिर गला घोंटा जाता है, और फिर विरोधी हार मान लेता है। यहाँ भी यही हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर भारत गठबंधन सरकार होती तो बातचीत का तरीका बिल्कुल अलग होता।

लोकसभा में राहुल गांधी पर भाजपा का हमला

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुबे ने मीडिया को बताया कि मैंने गुरुवार को लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैंने अपने प्रस्ताव में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।

यह प्रस्ताव गांधी के बुधवार को लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि विश्व एक वैश्विक संकट का सामना कर रहा है, एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है।

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला

मजदूरों-किसानों की आवाज नजरअंदाज हुई

नईदिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नई श्रम संहिताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण देश के मजदूरों और किसानों का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वे जनता की आवाज़ सुनेंगे या उन पर किसी बाहरी ग्रिप (पकड़) का प्रभाव बहुत मजबूत है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चार श्रम संहिताओं का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मजदूरों और किसानों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मज़बूत है? राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ''आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी।''

उनके मुताबिक, किसानों को आशंका है कि (अमेरिका के साथ किया गया) व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके (मजदूरों और किसानों के) भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, तब उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।''

उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मज़बूत है? राहुल गांधी ने कहा, '' मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं।

क्या हैं ये चार श्रम संहिताएं?

केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नई संहिताएं तैयार की हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष और ट्रेड यूनियन विरोध कर रहे हैं-

वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता।

सरकार का तर्क है कि ये सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, जबकि विपक्ष इसे पूंजीपतियों के पक्ष में और मजदूरों के शोषण का औजार बता रहा है।

न्यू इंडिया की नई पहचान सेवा तीर्थ

पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्र को समर्पित

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुराने ढांचे से काम कर रहे थे। इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमता, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। नए भवन परिसर आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं।

सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं।

दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। 4-स्टार गृह मानकों के अनुसार डिज़ाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। ये उपाय परिचालन दक्षता बढ़ाते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं। भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित करती हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 विश्व कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रनों से हराया

पल्लीकल। श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के 16वें मैच में 105 रन से बड़ी जीत दर्ज की है और 4 अंक के साथ नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है। श्रीलंका के लिए यह एक शानदार जीत साबित हुई, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। श्रीलंका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुसल मेंडिस, पवन रथनायके और दसुन शनाका के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। कुसल मेंडिस ने 45 गेंदों पर 61 रन बनाए जिसमें 7 चौके शामिल थे। वहीं रथनायके ने 28 गेंदों पर 8 चौकों और एक छक्के की मदद से 60 रन बनाए। शनाका ने 20 गेंदों पर 50 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ओमान की तरफ से जितेन रामानंदी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके जिसके लिए 41 रन दिए।

ओमान ने 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद नदीम की अर्धशतकीय पारी की बदौलत कड़ा मुकाबला किया लेकिन अन्य बल्लेबाजों की तरफ से साथ ना मिल पाने के कारण हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के गेंदबाजों ने कभी भी ओमान को गेम में बढ़त बनाने का मौका नहीं दिया। हालांकि इन सबके बीच में 43 वर्षीय मोहम्मद नदीम ने कुछ संघर्ष किया और विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। वसीम अली ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए और टीम ऑल आउट होने से भी बची क्योंकि ओमान ने 9 विकेट के नुकसान पर 120 रन पर पारी और मैच का अंत किया। दुशमंथा चमीरा ने पहले ही ओवर में विकेट लिया, महेश थीकशाना ने दूसरे ओवर में विकेट लिया और बाकी की पारी श्रीलंका के लिए एक औपचारिकता मात्र थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 557 अंक टूटा निफ्टी 25807 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार (12 फरवरी) को गिरावट में बंद हुए। इसी के साथ बाजार में पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया। एआई डिस्क्रप्शन से डर से भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते बाजार में गिरावट आई। इसके अलावा इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी गिरावट आई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ 83,968 अंक पर खुला और कारोबार के दौरान 83,516 अंक तक फिसल गया था। अंत में 558.72 अंक या 0.66% की गिरावट लेकर 83,674.92 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी गिरावट लेकर 25,906 पर खुला और सेशन के दौरान इसी स्तर के नीचे रहा। अंत में 146.65 अंक या 0.57% गिरकर 25,807 पर बंद हुआ।

एचयूएल का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ दोगुना हुआ

नई दिल्ली। घरेलू उपयोग का रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर दोगुना होकर 6,603 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एचयूएल ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपने आइसक्रीम व्यवसाय को क्वालिटी वॉल्स लिमिटेड को बेच दिया था जिससे उसके लाभ में यह वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने बताया कि नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से तिमाही के दौरान 576 करोड़ रुपए के असाधारण मद (हानि) दर्ज किए। कंपनी ने कहा, शुद्ध लाभ 6,603 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई। असाधारण मदों और कर से पहले इसका लाभ 3,495 करोड़ रुपए था।

सेल का 2025-26 में दो करोड़ टन बिक्री दर्ज करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में दो करोड़ टन बिक्री दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 1.79 करोड़ टन रही थी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी भविष्य के विस्तार की तैयारी के तहत ऋण घटाने, लागत नियंत्रण और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रही है। सेल के निदेशक (वित्त) डॉ. ए. के. पंडा ने बताया कि अप्रैल-दिसंबर 2025 की नौ महीने की अवधि में कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया है। 31 दिसंबर 2025 तक कुल ऋण 24,852 करोड़ रुपए था जिसमें जनवरी 2026 में 2,000 करोड़ रुपए की और कमी आई। उन्होंने कहा, परिचालन दक्षता, लागत अनुकूलन और मजबूत कोष प्रबंधन आदि से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और विकास निवेशों के लिए अवसर बने हैं।

आरबीआई के नए नियमों से ग्राहकों को राहत

नईदिल्ली। अगर आपने कभी बैंक से लोन लेते समय साथ में जबरन बीमा, क्रेडिट कार्ड या अन्य वित्तीय उत्पाद थमा दिए जाने का अनुभव किया है, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मिस-सेलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले भ्रामक तरीकों यानी 'डार्क पैटर्न' पर सख्ती करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इन नियमों के लागू होने के बाद बैंक ग्राहकों की स्पष्ट और अलग-अलग सहमति के बिना कोई अतिरिक्त प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। प्रस्तावित नियमों को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की योजना है। अब तक अक्सर देखा जाता था कि लोन या खाता खुलवाने के दौरान ग्राहकों को बिना पूरी जानकारी दिए बीमा, म्यूचुअल फंड या क्रेडिट कार्ड भी बेच दिए जाते थे।

कृषि उपज के लिए बाजार को खोलना यानी बवंडर को निमंत्रण

उमेश चतुर्वेदी

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे।

भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने सिर्फ 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के साथ कृषि कारोबार के चलते अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता

है। रोलिंग्स की इस खुशी की वजह से भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती-किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत के छियासी प्रतिशत किसान सीमांत या लघु हैं। जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। इससे भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है।

किसानों की आशंकाओं को विपक्षी दलों ने अपने ऊंचे सुरों से और बढ़ाया ही है। लेकिन कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों,सब्जियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, इस समझौते से भारतीय किसानों को नए अवसर मिलेंगे,क्योंकि इस समझौते में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से अमेरिका समेत कई देशों को करीब 63 हजार करोड़ के चावल का निर्यात कर चुका है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा।

भारत-अमेरिकी समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है।

2.36 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण

मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सशक्त माध्यमः कश्यप

रायपुर। नारायणपुर में आयोजित ऐतिहासिक माता मावली मेले में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने माता मावली की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों, विशेषकर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मावली माता के आशीर्वाद से बस्तर की समृद्ध लोकसंस्कृति और परंपराएं सदैव अक्षुण्ण रहें। उन्होंने कहा कि नारायणपुर का यह मेला सामाजिक समरसता, लोककला और परंपरा का जीवंत संगम है, जहां दूर-दूर से लोग पहुंचकर बस्तर की संस्कृति से रूबरू होते हैं। उन्होंने सभी को मेले में शामिल होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का आग्रह किया। मंत्री द्वय ने मेले में लगे विभिन्न दुकानों एवं विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्थानीय उत्पादों और पूजा सामग्री की खरीदारी भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर कुल 1 करोड़ 76 लाख 59 हजार रुपये के कार्यों का भूमिपूजन तथा 59 लाख 51 हजार रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 10 प्राथमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया, जिनकी स्वीकृत राशि 1 करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये है। इसके अलावा जनपद पंचायत ओरछा के ग्राम कुतुल एवं जाटलूर में दो-दो बाजार शेड निर्माण के लिए 34 लाख 99 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।

जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत बागडोंगरी, पालकी और महिमागवाड़ी में 59 लाख 51 हजार रुपये की लागत से निर्मित खाद्यान्न भवनों का लोकार्पण किया गया। साथ ही नेलवाड़ और खोड़गांव में 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

पीएम मोदी और शाह ने भाजपा में शामिल होने का बनाया था दबावः भूपेश बघेल

मना करने पर पड़े थे छापे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक दावे से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल, देश के सीनियर वकील कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। बघेल के दावे के मुताबिक, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न्योता देकर दिल्ली बुलाया था । इशारे- इशारे में ही बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जाता था पर उनके द्वारा आश्वासन नहीं दिए जाने पर और दिल्ली से उनके वापसी होने के कुछ ही दिनों बाद उनके परिजनों और करीबियों के यहां केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े थे।

साक्षात्कार में सनसनीखेज दावे

सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने पॉडकास्ट में पूर्व सीएम बघेल का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार में बघेल ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उनके अनुसार उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया था। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की थी। शुरू में जब उन्हें बुलाया गया तो उन्हें लगा कि सिर्फ औपचारिक भेंट होगी। जब वे मुलाकात करते थे तब औपचारिक बातों के अलावा मेरे और मेरे करीबियों के खिलाफ चल रहे केसों की जानकारी मांगते और मदद का आश्वासन देते थे। शुरूङ्कशुरू में तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कांग्रेस का सीएम होने के बावजूद मुझे मदद का आश्वासन क्यों दिया जाता था बाद में समझ में आया।

भाजपा में शामिल होने का इशारा

पूर्व सीएम बघेल का दावा है कि उन्हें इशारों- इशारों में भाजपा में शामिल होने के लिए कहा जाता था। यह इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से था। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा था कि मैं विपक्ष में हूं और विपक्ष का धर्म होता है सरकार की आलोचना करना और वह मैं निभाता रहूंगा। इसके बाद भी मुझे मदद का ऑफर दिया जाता था। पूछा जाता था कि कौन से अधिकारी भरोसेमंद है और किस तरह से मदद की जा सकती है। जबङ्कजब वह दिल्ली से दोनों नेताओं से मुलाकात करके आते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर उनके और उनके करीबियों के यहां छापे पड़ जाते थे। शुरू मे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन किया था।

भूपेश बघेल के दावे के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने फोन कर कहा कि आपसे मुलाकात में आपने मदद का वादा किया था पर उल्टे मेरे यहां तो छापा पड़ गया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया था। दोनों नेताओं से मुलाकात में बीजेपी ज्वॉइन करने के लिए कोई कमिटमेंट करके नहीं आया था। इस वजह से उन्हें और उनके करीबियों को परेशान किया गया। उनके यहां लगातार छापे पड़े। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस दावे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही हैं।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़

राज्य में 10,796 हेक्टेयर क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती

रायपुर। खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 10,796 हेक्टयर क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती हो रही है। जिसमें 7,315 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जिला प्रशासन भी ऑयल पाम के लिए जमीन चिहांकित कर रकबा बढ़ाने प्रयासरत हैं।

इसी क्रम में संचालक उद्यानिकी श्री लोकेश कुमार ने दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों के किसानों के खेतों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। उद्यानिकी संचालक लोकेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन, समेकित उद्यानिकी विकास कार्यक्रम तथा नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। गौरतलब है कि राज्य में ऑयल पाम की खेती वर्ष 2012-13 से की जा रही है। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में लगभग 10,796 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया जा चुका है, जिससे 7,315 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा फ्रेश फ्रूट बंच का न्यूनतम मूल्य 16,460.46 रुपये प्रति टन निर्धारित कया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों से 22,000 रुपये प्रति टन की दर से सीधी खरीदी की जा रही है।

संचालकलोकेश कुमार ने दुर्ग जिले के ग्राम ढाबा में श्रीमती सुनिती देवी मढरिया के एक हेक्टेयर में लगाए गए ऑयल पाम के साथ टमाटर की अंतरवर्ती फसल तथा श्री प्रवीण मढरिया के एक हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम के साथ केले की खेती का अवलोकन किया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य उन्नत वेतन पैकेज के लिए हुआ एमओयू

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को 'गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम' के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे। समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक करोड़ 25 लाख रूपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर एक करोड़ 25 लाख रूपए तक तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रूपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रूपए तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रूपए तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा श्री वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सुखद अनुभूति हुईः संजीव शुक्ला

छः दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव शान्ति सरोवर में शुरू

पुलिस कमिश्नर, महापौर और निगम सभापति ने किया उद्घाटन

रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा शान्ति सरोवर सड्डू में आयोजित छः दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिप्ती शुक्ला, महापौर श्रीमती मीनल चौबे और निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी किरण और भावना दीदी भी उपस्थित थीं।

पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पन्द्रह फीट ऊंचे पहाड़ पर प्रदर्शित द्वादश ज्योर्तिलिंग की सराहना करते हुए कहा कि इसे देखकर बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। एक ही छत के नीचे द्वादश ज्योतिर्लिंग का अवलोकन करके अच्छा लगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग को आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास अच्छा है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग को देखकर असीम शान्ति की अनुभूति हुई। सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की मनमोहक प्रस्तुति दिल को छू लेने वाली है। भगवान शिव की झांकी सभी के लिए प्रेरणादायी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा ने आदिवासियों पर प्राण घातक हमला किया : बैज

रायपुर। बालोद जिला में भाजपा नेताओं पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को राजनीतिक बताकर वापस लिए जाने को पीड़ितों के साथ अन्याय करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने नेताओं पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को राजनीतिक बताकर वापस ले रही है, ये पीड़ित आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय है। प्रकरण वापस होने की खबर के बाद आक्रोशित आदिवासी समाज ने बालोद कलेक्टर का घेराव कर विरोध जताया, न्याय की मांग की। 1 मई 2022 को आदिवासी समाज जो अपनी परम्परा का निर्वहन कर रहे उन पर भाजपा नेताओं ने समूह बनाकर हमला किया था। आरोपियों पर तुएगोंदी गांव के आदिवासी वर्ग के साथ तलवार, चाकू, लाठी लेकर मारपीट करने, जान से मारने, गम्भीर चोट पहुँचाने, हत्या का प्रयास करने का गम्भीर आरोप है, जिस पर बालोद जिला के थाना मुंगघुवा में दर्ज अपराध क्रमांक 16/22 प्रकरण क्रमांक 58/23 जिस पर धारा 307, 120बी, 147, 148, 149, 294, 323, 506, 25, 27, आर्म्स एक्ट, एवं 3(2)(ट) एससी/एस टी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। आदिवासी वर्ग के साथ अत्याचार करने वाले अपराधी किस्म के लोगों को जिसे न्यायालय सजा देगी।

मोदी की गारंटी निकली झूठी नहीं मिला एक मुश्त राशिः ठाकुर

रायपुर। किसानों को धान की कीमत 3100 रु प्रति क्विंटल एकमुश्त देने की गारंटी को झूठा करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। किसानों को मोदी की गारंटी थी कि धान बेचते ही 3100 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान बेचते ही पंचायत भवन में नगद भुगतान किया जायेगा, जो बीते दो साल में पूरा नही हुआ है। किसानों के लिए मोदी गारंटी झूठा साबित हो गया। भाजपा अपने सबसे बड़े नेता की किसानों को दी गई गांरटी को तोड़ दिया। कांग्रेस ने पहले ही कहा था धान बेचने वाले किसानों को 3100 रु. की दर से भुगतान नहीं हो रहा है। आज आरोप सच साबित हुआ है। जब भाजपा सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी के बाद 3100 रु. की बकाया राशि होली त्यौहार में देने की घोषणा की है। भाजपा की कथनी और करनी में यही अंतर है। मोदी की गारंटी थी सभी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी जायेगी, लेकिन चालू खरीफ सीजन में किसान धान बेचने परेशान रहे है। अभी भी 7 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से लगभग 23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी नही की गई। 16 लाख से अधिक किसानों का 5 लाख 50 हजार करीब रकबा कटौती कर प्रति एकड़ 21 किवंटल धान की खरीदी नही की गई। किसानों धान

शराबखोरी को बढ़ावा दे रही सरकारः वर्मा

रायपुर। बार-बार बदले जा रहे आबकारी नीति और नए-नए शराब दुकान खोलने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ साय सरकार लगातार नई शराब दुकानें खोल रही है, दूसरी तरफ इस सरकार में पुलिस ही ड्रग्स की तस्करी कर रही है। इस सरकार की नियत और जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ है, मुनाफाखोरी के लालच में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में नकली शराब, अवैध शराब, गुणवत्ताहीन शराब के साथ ही सूखे नशे का कारोबार पूरे प्रदेश में फल-फूल रहा है, गांजा, नशीली दवाएं और नशे के पाउडर सीमा पार से लाकर छत्तीसगढ़ में बेचे जा रहे हैं, सरकार खुद ही नए-नए शराब दुकान खोल कर शराबखोरी को बढ़ावा दे रही है। इस जनविरोधी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 1 अप्रैल से फाइबर की बोतल में शराब मिलेगी। 35 नई दुकानों के शटर भी खोले जाएंगे। शराब की काली कमाई के लालच में भाजपा की सरकार ने पिछले दो वर्षों में आधा दर्जन बार आबकारी नीति में परिवर्तन किया है। पूर्व में संचालित लगभग 700 दुकानों में कंपोजिट व्यवस्था लागू करके अंग्रेजी में देसी और देसी शराब दुकानों में अंग्रेजी शराब भी बेचने का निर्णय लिया अर्थात पुरानी दुकानों की क्षमता दुगनी की।

होली से पहले भुगतान के लिए आभारः द्विवेदी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की है, जिसका समर्थन मूल्य के तहत भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में 11 फरवरी को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में होली त्यौहार से पहले किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि देने का निर्णय लिया है। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्राधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस वर्ष प्रदेश के 25.24 लाख से अधिक किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की है। धान के एवज में मार्कफेड द्वारा किसानों के बैंक खाते में 31 हजार 275 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार बीते तीन खरीफ विपणन सीजन से किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए की मान से धान खरीदी कर अपने वायदे को पूरा कर रही है। मंत्री परिषद के इस निर्णय से किसानों में उत्साह का माहौल है। होली त्यौहार के पहले ही अंतर की राशि का भुगतान होने होली त्यौहार की खुशी का उत्साह और दोगुनी हो जाएगी।

होली से पहले बरसेगा खुशियों का गुलाल : ठाकुर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य के लाखों किसानों को होली पर्व से पहले धान की अंतर राशि (3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से) का एकमुश्त भुगतान करने के फैसले को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार, राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों को होली के पावन पर्व से पहले अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में रिकॉर्ड 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार केवल धान नहीं खरीद रही, बल्कि किसानों के पसीने की एक-एक बूंद की कीमत चुकाकर उनके पुरुषार्थ का सम्मान कर रही है। ?मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश का 'अन्नदाता' ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। होली से पहले एकमुश्त भुगतान का निर्णय किसानों के जीवन में न केवल आर्थिक संबल लाएगा, बल्कि उनके उत्सव के उल्लास को दोगुना कर देगा। मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का 22वां स्थापना दिवस

योजनाओं की समीक्षा, गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने आज अपना 22वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। राज्य गठन के बाद 12 फरवरी 2004 को मंडल का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन के पश्चात अब तक मंडल द्वारा निर्मित लगभग एक लाख आवासों एवं संपत्तियों में से करीब 75 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए तैयार किए गए हैं।

स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव और आयुक्त अवनीश शरण ने सभी शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। अध्यक्ष सिंह देव ने हाउसिंग बोर्ड परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बेहतर कार्य संस्कृति और हितग्राहियों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने रिव्यू, रिफॉर्म और रिवोल्यूशन की कार्यसंस्कृति अपनाने पर बल दिया।

अध्यक्ष ने बताया कि वर्षों से रिक्त पड़ी संपत्तियों में से 70 प्रतिशत का विक्रय किया जा चुका है। शेष 30 प्रतिशत संपत्तियों के शीघ्र विक्रय के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य भी शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित कॉलोनियों में ऐसे भूखंड, जो मंडल के उपयोग में नहीं हैं या अतिरिक्त रूप में आबंटित किए जा सकते हैं, उनका त्वरित निराकरण किया जाए।नई आवासीय योजनाओं के तहत विक्रय हो रहे मकानों की साइट पर एक टिन शेड कार्यालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, जहां परियोजना से संबंधित सभी जानकारी और ब्रोशर उपलब्ध कराए जाएं।मंडल द्वारा हाल ही में 2060 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 में 1023.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया, वहीं चालू वर्ष के मात्र 40 दिनों में ही लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय किया जा चुका है।आयुक्त अवनीश शरण ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध प्रगति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी शाखाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से आम जनता तक पहुंच सके।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा कार्यों की समीक्षा को सकारात्मक पहल बताते हुए अध्यक्ष, आयुक्त और पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

लाभांडी से सरोना तक सर्विस लेन चौड़ीकरण को मिली मंजूरी

रायपुर। रायपुरवासियों और मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-53 का उपयोग करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सरोना से लाभांडी के बीच सर्विस लेन के चौड़ीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 14.25 किलोमीटर लम्बाई में दोनों ओर के सर्विस लेन की चौड़ाई 10-10 मीटर की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर की इस बहुप्रतीक्षित जरूरत के पूरा होने पर केंद्र सरकार और केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ओर के सर्विस रोड का चौड़ीकरण रायपुरवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इससे शहर के बीच यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या घटेगी और लोगों का समय बचेगा। शहर के भीतरी और बाहरी दोनों मार्गों पर सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात हमारी प्राथमिकता है।

राजधानी रायपुर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के दोनों ओर के सर्विस लेन के चौड़ीकरण से लाभांडी, तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर, भाठागांव अंतरराज्यीय बस स्टैंड और सरोना जैसे हाइवे से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी इस मार्ग पर चौबीसों घंटे भारी वाहनों का दबाव रहता है, जिससे स्थानीय यातायात प्रभावित होता है और अक्सर जाम की स्थिति बनती है। सर्विस लेन की चौड़ाई दोगुनी होने से स्थानीय व्यापारियों को लोडिंग-अनलोडिंग में सहूलियत होगी। साथ ही इस मार्ग से रोजाना आना-जाना करने वाले हजारों वाहन चालकों का समय भी बचेगा।शहर के बीच क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना में सड़क चौड़ीकरण के लिए किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.